ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज

सच्ची खबर सबसे पहले

आर.एन.आई. नं. :- CHHHIN/2021/82386

online- jwalaexpress.com

वर्ष - 05, अंक -36 | दुर्ग (छ.ग.), दिनांक 07 मई से 13 मई (प्रत्येक गुरूवार) | पृष्ठ - 8, मूल्य - 05 रुपए

संक्षिप्त समाचार

ओडिशा में ससुराल के घर के सामने धरने पर बैठी महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या

गंजम। ओडिशा के गंजाम जिले में एक गर्भवती महिला की कथित तौर पर निर्मम हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम उस समय दिया गया महिला जब महिला अपनी बेटी के हक की मांग को लेकर ससुराल में घर के सामने धरने पर बैठी थी. इस घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया. पुलिस ने बताया कि मृतक और आरोपी की पहचान हो गई है. आरोपी शख्स महिला का देवर है. उसे हिरासत में लिया गया. वारदात के समय महिला का पति घर पर नहीं था. उस समय महिला अपनी 2 साल की बेटी के साथ ससुराल के घर के सामने धरने पर बैठी थी. बताया जाता है कि महिला का पति कुछ समय पहले उसे छोड़कर चला गया था. महिला अपनी बेटी के हक की मांग करते हुए अपने ससुराल घर के सामने धरना दे रही थी. पुलिस के अनुसार वह प्रेग्नेंट भी थी. पुलिस के अनुसार मर्डर केस दर्ज कर लिया है

कश्मीर घूमने आए अमेरिकी नागरिक की श्रीनगर में मौत

श्रीनगर। कश्मीर घूमने आए एक 83 साल के अमेरिकी नागरिक की आज अचानक मौत हो गई. खबर के मुताबिक, वह सुबह श्रीनगर में डल झील के हाउसबोट में बेहोश होकर अचानक गिर पड़े और उनकी मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. अधिकारियों ने मृतक की पहचान एंडरसन जॉन डेविड के तौर पर की है. वह अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के रहने वाले जॉन डेविड के बेटे थे. श्रीनगर में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मरने वाले के बीमार पड़ने पर हाउसबोट मालिकों और दूसरे लोगों ने उन्हें पास के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी पत्नी और एक और जान-पहचान वाले भी थे. अधिकारी ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें आते ही मृत घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि शव को एसएमएचएस अस्पताल और बाद में आगे की कानूनी और मेडिकल प्रक्रिया के लिए शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में शिफ्ट कर दिया गया.

शशि शेखर वेम्पति सीबीएफसी के नए अध्यक्ष नियुक्त

नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया विशेषज्ञ शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब भारतीय फिल्म का दायरा तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय सिनेमा, ओटीटी और वैश्विक सहयोग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में सेंसर बोर्ड की भूमिका और जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। शशि शेखर भारत के प्रमुख मीडिया और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने प्रसार भारती के सीईओ पद पर अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। उनकी अगुवाई में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया। इससे पहले वह इंफोसिस और डिजिटल न्यूज स्टार्टअप नीति डिजिटल से जुड़े थे।

सुशासन तिहार 2026

मुख्यमंत्री साय ने मुंगेली को दी 353 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

रायपुर। प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत आज मुंगेली जिला विकास, जनकल्याण और सुशासन के एक ऐतिहासिक अध्याय का साक्षी बना। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जिला मुख्यालय स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में शामिल होकर जिले को 353 करोड़ 58 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले 414 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 152 करोड़ 02 लाख रुपये से अधिक की लागत के 284 कार्यों का लोकार्पण तथा 201 करोड़ 56 लाख रुपये से अधिक की लागत के 130 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इन कार्यों से जिले में आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और जनसुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी।

कार्यक्रम में केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, वाणिज्य एवं उद्योग, श्रम तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक, मुंगेली विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले, तखतपुर विधायक श्री धरमजीत सिंह, बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री श्रीकांत पाण्डेय, नगर पालिका अध्यक्ष श्री रोहित शुक्ला सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम के दौरान पुष्प वाटिका एवं चौपाटी, नहर, एनीकट, लाइवलीहुड कॉलेज भवन पहुंच मार्ग, मुंगेली-भटगांव पहुंच मार्ग सहित अनेक सड़क निर्माण कार्यों, महतारी सदनों, छात्रावासों, जल जीवन मिशन के कार्यों, सामुदायिक भवनों, अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों, प्राथमिक शाला भवनों, सांस्कृतिक मंचों, सीसी सड़कों, अमृत सरोवरों तथा आंगनबाड़ी भवनों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही विभिन्न ग्रामों में सीसी सड़क, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सड़क मार्ग, एसटीपी निर्माण, तालाब सौंदर्यीकरण, फुटपाथ और पुल निर्माण सहित अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद विद्यालय मोतिमपुर, लालपुरथाना, लोरमी, पथरिया और सरगांव का वर्चुअल लोकार्पण भी किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन सरकार विकास और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज मुंगेली जिले को मिली विकास कार्यों की यह बड़ी सौगात आने वाले समय में जिले के विकास को नई गति प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से आमजनों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है तथा शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर भक्ति और श्रम की प्रतीक माता कर्मा, सामाजिक समरसता के प्रतीक बाबा गुरु घासीदास, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर तथा शौर्य और त्याग के प्रतीक महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का अनावरण करते हुए कहा कि ये महापुरुष समाज को प्रेरणा देने वाले आदर्श हैं। उन्होंने नवागढ़ रोड में वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापना के लिए 25 लाख रुपये, मुंगेली में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास भवन निर्माण, मेला नवागांव में बाउंड्रीवाल एवं प्रवेश द्वार निर्माण के लिए 20 लाख रुपये तथा सीसी सड़क निर्माण के लिए 10 लाख रुपये की घोषणा की। साथ ही चिकित्सा महाविद्यालय की मांग को पूरा करने के लिए सकारात्मक आश्वासन दिया।

बाल-बाल बचे उपमुख्यमंत्री

एकनाथ का हेलीकॉप्टर आसमान में फंसा रहा...

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुरुवार को एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गए। शिंदे का हेलीकॉप्टर मुंबई के पास कल्याण के आसमान में था तभी अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज आंधी-तूफान ने विमान को घेर लिया। पायलट की त्वरित कार्रवाई और सूझबूझ की वजह से एक बड़ा विमान हादसा टल गया। उपमुख्यमंत्री शिंदे का हेलीकॉप्टर अचानक ठाणे के कल्याण के पास तेज हवाओं और तूफान में फंस गया। पायलट ने तेजी दिखाते हुए बिगड़ते मौसम के हालात का जायजा लिया और हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे न बढ़ने का फैसला किया। कम विजिबिलिटी, तेज हवाओं और अस्थिर मौसम के कारण पायलट ने एहतियात के तौर पर हेलीकॉप्टर को वापस मुंबई की ओर मोड़ने का फैसला किया।

जंगल से निकल रहा काला खजाना

सुरक्षा बलों की सर्चिंग में खुल रहे माओवादियों के गुप्त राज बस्तर में 50 करोड़ से ज्यादा पूंजी छिपे होने का अंदेशा है....

- बीते तीन महीनों में जवानों ने करीब 6 करोड़ 75 लाख रुपए नगद और 8 किलो सोना बरामद किया है।

जगदलपुर। बस्तर में माओवादी नेटवर्क के कमजोर पड़ने के साथ अब उनके आर्थिक ढांचे की परतें खुलने लगी है। सुरक्षा बलों की लगातार सर्चिंग में ऐसे डंप सामने आ रहे हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि संगठन सिर्फ बंदूक के दम पर नहीं बल्कि मजबूत आर्थिक जाल पर भी टिका था। बीते तीन महीनों में जवानों ने करीब 6 करोड़ 75 लाख रुपए नगद और 8 किलो सोना बरामद किया है, जो इस छिपे खजाने की एक झलक भर है। आईजी सुंदरराज पी के मुताबिक, यह बरामदगी अंदरूनी इलाकों में छिपाकर रखे गए डंप से हुई है, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। जानकार बताते हैं कि नोटबंदी के बाद माओवादियों ने रणनीति बदली और नगद की जगह सोने में निवेश करना शुरू किया, ताकि जोखिम कम रहे। बरामद 8 किलो सोने की कीमत ही करीब 13 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिससे संगठन की आर्थिक ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह पैसा तेंदूपत्ता संग्राहकों, ठेकेदारों और विकास कार्यों में लगे लोगों से लेवी के रूप में वसूला जाता था, जो साल दर साल करोड़ों में पहुंचता था। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी मानते हैं कि अब तक मिली रकम सिर्फ सतह है, असल में बस्तर में ही माओवादियों की छिपी पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। यानी जैसे-जैसे माओवादी नेटवर्क खत्म हो रहा है, वैसे-वैसे उनका आर्थिक साम्राज्य भी उजागर हो रहा है। हालांकि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, क्योंकि जंगलों में छिपे ऐसे कई डंप अब भी सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं। फिलहाल बस्तर में जारी सर्च ऑपरेशन सिर्फ हथियारों की तलाश नहीं, बल्कि माओवादियों की उस आर्थिक रीढ़ को तोड़ने की कोशिश भी है, जिस पर उनका पूरा नेटवर्क खड़ा था।

बिहार में हुआ कैबिनेट विस्तार-पीएम मोदी रहे मौजूद

सम्राट चौधरी सहित कुल 32 मंत्रियों ने ली शपथ...

पटना/ एजेंसी

बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया पूरी की गई। पटना में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली कैबिनेट का विस्तार किया गया। गांधी मैदान में सम्राट चौधरी और उनकी कैबिनेट में कुल 32 मंत्रियों ने मंत्री पद और गोपनियता की शपथ ली। बिहार में कैबिनेट विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राजनाथ सिंह और कई अन्य नेता उपस्थित रहे। बिहार के लिए अहम चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, श्रवण कुमार, निशान्त कुमार और लेसी सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इसी क्रम में रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, दामोदर रावत, संजय सिंह टाइगर, अशोक चौधरी ने शपथ ली। इसके अलावा पटना के गांधी मैदान में रमा निषाद, रत्नेश सदा, कुमार शैलेन्द्र, शीला कुमारी, भगवान सिंह कुशवाहा, अरुण शंकर प्रसाद, मदन सहनी, डॉ. संतोष कुमार सुमन, केदार प्रसाद गुप्ता और लखेन्द्र कुमार रौशन ने बिहार के मंत्री पद की शपथ ली। पटना में सुनील कुमार, श्रेयसी सिंह, मोहम्मद जमा खान, नंद किशोर राम, शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल और प्रमोद कुमार ने बिहार के मंत्री पद की शपथ ली।

ग्वालियर में शादी से लौट रहे दोस्तों की कार बनी आग का गोला, 2 की मौत

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बुधवार को एक चलती कार में आग लग गई, जिससे उसमें सवार 2 लोग जिंदा जल गए। हादसा डाबरा इलाके में हुआ है। घटना के समय तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई, जिसके बाद उस पर बिजली के तार गिर पड़े। बताया जा रहा है कि 11केवी बिजली के खंभे से तार गिरने पर पूरी कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग का गोला बन गई।छतरपुर निवासी अवधेश विश्वकर्मा (32) और रामजी सोनी (33) शिवपुरी आए थे। यहां अवधेश के बहनोई अविनाश झा (29) रहते हैं। तीनों ग्वालियर में दोस्त की शादी में गए थे।

भ्रष्टाचार पर शी जिनपिंग का सबसे बड़ा प्रहार

चीन में 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को मिली मौत की सजा...

चीन/ एजेंसी

चीन की राजनीति और सेना में तब खलबली मच गई जब वहां की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने खबर दी कि दो पूर्व रक्षा मंत्रियों को मौत की सजा सुनाई गई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे अभियान में इसे अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई माना जा रहा है। चीनी अधिकारियों के मुताबिक, पूर्व रक्षा मंत्री वेई फेंगहे और उनके बाद पद संभालने वाले ली शांगफू को भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में दोषी पाया गया है। अदालत ने दोनों को मौत की सजा दी है लेकिन इसमें दो साल की छूट दी गई है। चीन की सेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब लगातार दो रक्षा मंत्रियों को इतनी बड़ी और कड़ी सजा मिली है। 2023 में ली शांगफू अचानक गायब हो गए थे। उन पर सेना की जांच एजेंसियों ने नियमों के गंभीर उल्लंघन के आरोप लगाए थे। जांच में यह पता चला कि उन्होंने अपने फायदे के लिए बहुत सारा पैसा और कीमती चीजें रिश्वत में लीं और सेना में नियुक्तियों के दौरान पक्षपात किया। उन्हें पहले ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और ताकतवर केंद्रीय सैन्य आयोग से बाहर निकाला जा चुका था। ली शांगफू से पहले रक्षा मंत्री रहे वेई फेंगहे को भी इन्हीं आरोपों की वजह से पार्टी से निकाल दिया गया था।

अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी समाज के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री

देश की प्रगति और राष्ट्रीय एकता में क्षत्रिय कुर्मी समाज का योगदान अविस्मरणीय : मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज कबीरधाम जिले के डोंगरिया में आयोजित अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी समाज के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने समाज की एकता, संगठन, सामाजिक चेतना तथा देश और प्रदेश के विकास में कुर्मी समाज के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि एक संगठित और सशक्त समाज ही मजबूत राष्ट्र की आधारशिला होता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों को सिंचाई, सड़क और धार्मिक पर्यटन से जुड़े महत्वपूर्ण विकास कार्यों की सौगात भी दी। इससे पूर्व उन्होंने जलेश्वर महादेव धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया तथा प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कुर्मी समाज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जैसी महान विभूतियों ने देश की एकता, सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि कुर्मी समाज मेहनतकश, प्रगतिशील और जागरूक समाज है, जिसने खेती-किसानी से लेकर शिक्षा, प्रशासन और सामाजिक नेतृत्व तक हर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण के नए दौर से गुजर रहा है। अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर निर्माण करोड़ों देशवासियों की आस्था का प्रतीक बना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार रामलला दर्शन योजना के माध्यम से श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन करा रही है तथा अब तक लगभग 42 हजार श्रद्धालु इसका लाभ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को भी पुन: प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को देश के 19 प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक 27 किश्तों का भुगतान किया जा चुका है, जिससे प्रदेश की लाखों मातृशक्ति के खातों में 27-27 हजार रुपये की राशि पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 हजार 500 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिससे कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी। रेलवे अधोसंरचना के विस्तार और आधुनिकीकरण पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश की पांच प्रमुख शक्ति पीठों को विकसित कर धार्मिक और सांस्कृतिक कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ने की दिशा में भी सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जो समाज शिक्षित और संगठित होता है, वही निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित करता है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि समाज की वास्तविक शक्ति उसकी एकता और संगठन में निहित होती है। उन्होंने कहा कि जिस समाज के प्रेरणास्रोत छत्रपति शिवाजी महाराज और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे महानायक हों, वह समाज स्वाभाविक रूप से गौरवशाली और प्रगतिशील बनता है। उन्होंने समाज से शिक्षा, संगठन और सामाजिक समरसता को और मजबूत करने का आह्वान किया।

जल-जंगल-जमीन पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे

डिपाजिट-4 में सड़क निर्माण के खिलाफ फूटा आदिवासी आक्रोश, पहाड़ पर पहुंचे सरपंच

जनप्रतिनिधि, बोले - फर्जी ग्रामसभा कर खनन थोपने की कोशिश बर्दाश्त नहीं

बिना सूचना सड़क निर्माण, लाखों पेड़ों और जल स्रोतों पर खतरे का आरोप; डिपाजिट-4 में विरोध तेज

दंतेवाड़ा :- डिपाजिट-4 खदान क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क निर्माण और खनन गतिविधियों को लेकर अब विरोध खुलकर सामने आने लगा है। जल, जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई अब ग्रामीणों से निकलकर जनप्रतिनिधियों तक पहुंच गई है। क्षेत्र के सरपंच, जनपद प्रतिनिधि और ग्रामीण पहाड़ क्षेत्र में पहुंचकर सड़क निर्माण कार्य का विरोध जताया और खनन परियोजना को आदिवासी अस्तित्व के लिए खतरा बताया।

कुछ दिन पहले जहां सीपीआई नेता मनीष कुंजाम और समाजसेवी सोनी सोढ़ी ने डिपाजिट-4 में खनन गतिविधियों का विरोध किया था, वहीं अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। ÷बिना ग्रामसभा, बिना अनुमतिऽ किसके आदेश पर बन रही सड़क?

ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि NMDC Limited और CMDC Limited द्वारा डिपाजिट-4 क्षेत्र में बिना ग्रामसभा, बिना स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहमति और बिना ग्रामीणों को सूचना दिए सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया जा रहा है। उनका कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया पंचायत कानून और आदिवासी क्षेत्रों के अधिकारों की खुली अनदेखी है। बताया जा रहा है कि डिपाजिट-4 क्षेत्र में लगभग 646.596 हेक्टेयर भूमि पर खनन की तैयारी चल रही है। इसी को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष अरविंद कुंजाम, बड़े कमेली सरपंच करण तामो, जनपद उपाध्यक्ष रमेश गावड़े, नेरली सरपंच रवि तेलाम और गमावाड़ा सरपंच सुनील भास्कर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण पहाड़ क्षेत्र पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया।

72 साल से खनन, लेकिन गांव अब भी बदहाल- जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि NMDC Limited पिछले 72 वर्षों से क्षेत्र में खनन कर रही है और अब 53 मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, लेकिन आज भी आसपास के पंचायत क्षेत्रों और गोद ग्रामों में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है।

ग्रामीणों का कहना है कि आज भी कई गांव प्राकृतिक जल स्रोतों और जंगलों पर निर्भर हैं। ऐसे में बड़े स्तर पर खनन परियोजना शुरू होने से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाएगा और आदिवासी समुदाय के जीवन पर गंभीर असर पड़ेगा।

लाखों पेड़ कटेंगे, जल स्रोत सूखेंगे- विरोध कर रहे ग्रामीणों ने दावा किया कि जिस पहाड़ी क्षेत्र में खनन की तैयारी चल रही है वहां घने जंगल, दुर्लभ वन्यजीव और प्राकृतिक जल स्रोत मौजूद हैं। उनका कहना है कि सड़क निर्माण और खनन परियोजना से लाखों पेड़ों के कटने, जल स्रोतों के प्रभावित होने और वन्यजीवों के अस्तित्व पर खतरा पैदा होने की आशंका है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ÷फर्जी ग्रामसभा÷ के जरिए परियोजना को वैध दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वास्तविक ग्रामीणों से कोई राय नहीं ली गई।

अब नहीं चलेगी चिकनी-चुपड़ी बातें- मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि जब तक स्थानीय ग्रामीणों के विकास, पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं का पूरा हिसाब नहीं दिया जाता तथा ग्रामसभाओं की वास्तविक सहमति नहीं ली जाती, तब तक डिपाजिट-4 में किसी भी प्रकार का खनन कार्य नहीं होने दिया जाएगा।

ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा— अब आदिवासी समाज किसी बहकावे में आने वाला नहीं है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा।÷

भाजपा नेता और सरपंच पति पर दुष्कर्म का आरोप पीड़िता ने पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप

भानुप्रतापपुर। जिले के दुर्गुकोंदल ब्लॉक से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां भाजपा किसान मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष और सरपंच पति कैलाश नेताम पर एक 49 वर्षीय विवाहित महिला ने दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और डराने-धमकाने का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने अपनी जरूरत के समय आरोपी कैलाश नेताम को दो किस्तों में लगभग 1.50 लाख रुपये उधार दिए थे। जब पीड़िता ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने कथित रूप से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता ने बताया कि 19 मार्च 2026 दोपहर लगभग 3:30 बजे आरोपी पीड़िता के घर पहुंचा और जबरदस्ती उसे घर के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का दावा है कि गांव में हुई एक बैठक के दौरान आरोपी ने खुद अपना अपराध स्वीकार किया और चुनौती दी कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कांकेर को एक शिकायत पत्र लिखकर भानुप्रतापपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि उसने 18 अप्रैल 2026 को ही थाना भानुप्रतापपुर में एफआईआर दर्ज कराई हैं, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। शिकायती पत्र के अनुसार, आरोपी कैलाश नेताम बेखौफहोकर गांव में घूम रहा है और पुलिस केवल लापरवाही बरत रही है। एक गरीब आदिवासी महिला होने के नाते पीड़िता ने न्याय और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

भाजपा नेताओं के संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद, आदिवासी महिला को न्याय देने में पुलिस बरत रही कोताही : रामरतन नेताम

दुर्गुकोंदल ब्लॉक में भाजपा किसान मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष और सरपंच पति कैलाश नेताम पर लगे दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोपों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार और स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। दुर्गुकोंदल कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रामरतन नेताम ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस घटना की कड़ी निंदा की है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रामरतन नेताम ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में उनके नेताओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे कानून का डर भूल चुके हैं। उन्होंने कहा, एक 49 वर्षीय विवाहित आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म, उसे ब्लैकमेल करना और फिर सार्वजनिक रूप से अपराध स्वीकार कर चुनौती देना यह दर्शाता है कि आरोपी को सत्ता का खुला संरक्षण प्राप्त है। कैलाश नेताम जैसा व्यक्ति, जो भाजपा किसान मोर्चा का पदाधिकारी है, एक गरीब महिला के पैसे हड़पने और उसकी अस्मत से खेलने का दुस्साहस कर रहा है। रामरतन नेताम ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार के राज में आदिवासी महिलाएं असुरक्षित हैं। यदि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो कांग्रेस कमेटी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।

बांसला के जंगलों में एएनआर कार्य में भ्रष्टाचार की गूंज 22 लाख के भुगतान के बाद भी काम अधूरा

भानुप्रतापपुर। पूर्व वन मंडल भानुप्रतापपुर के अंतर्गत ग्राम बांसला में वनों के पुनरुद्धार के नाम पर शासकीय राशि के बंदरबांट का एक गंभीर मामला सामने आया है। जागरूक नागरिकों और पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वन विभाग के अधिकारियों और फर्मों की मिलीभगत से लगभग 22 लाख रुपये की सामग्री का भुगतान तो कर दिया गया है, लेकिन धरातल पर काम आधा-अधूरा है। इस मामले में मुख्य वन संरक्षक कांकेर को लिखित शिकायत सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम बांसला के जंगलों में पिछले वर्ष कूप कटाई के बाद ए.एन.आर. कार्य स्वीकृत हुआ था। इसका उद्देश्य कटे हुए वनों को फेंसिंग और उचित रखरखाव के जरिए पुनर्जीवित करना था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संबंधित फर्मों को मटेरियल सप्लाई के नाम पर करीब 22 लाख रुपये की पूरी राशि जारी कर दी गई है। जबकि मौके पर केवल आधी सामग्री ही पहुंचाई गई है। सामग्री की कमी के कारण घेराबांदी का कार्य अधूरा पड़ा है। सुरक्षित फेंसिंग न होने से नए पौधों और वन क्षेत्र को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे शासन की योजना विफल साबित हो रही है। शिकायत में मजदूरी भुगतान में भी भारी धांधली का जिक्र है। आरोप है कि ऐसे ग्रामीणों के नाम पर मस्टर रोल और वाउचर भरे जा रहे हैं, जिन्होंने कभी कार्यस्थल पर पैर तक नहीं रखा।

अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका

स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि बीट गार्ड से लेकर विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों तक इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। यही कारण है कि बिना भौतिक सत्यापन के ही इतनी बड़ी राशि का भुगतान कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि कार्यस्थल का निष्पक्ष निरीक्षण कराया जाए और फर्मों को दिए गए भुगतान का स्टॉक से मिलान किया जाए। शिकायतकर्ता ने सीसीएफ कांकेर से आग्रह किया है कि एक विशेष जांच टीम गठित कर दोषियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाए। अब देखना यह है कि विभाग अपने ही महकमे में व्याप्त इस 'दीमक' पर क्या कार्रवाई करता है।

कांग्रेस के तीखे तेवरों के आगे झुका प्रशासन: दुर्गुकोंदल में अवैध रेत खदान पर बड़ी कार्रवाई, 7 हाईवा और 2 चेन माउंटेन जब्त

भानुप्रतापपुर। दुर्गुकोंदल ब्लॉक में लंबे समय से चल रहे अवैध रेत खनन के काले कारोबार पर आखिरकार प्रशासन का डंडा चला है। कांग्रेस की आक्रामकता और ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश के बाद नींद से जागे माइनिंग विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 हाईवा और 2 चेन माउंटेन मशीनों को मौके से जब्त कर लिया है। गौरतलब है कि दुर्गुकोंदल ब्लॉक में अवैध रेत उत्खनन का खेल महीनों से जारी था। इसे रोकने के लिए स्थानीय ग्रामीणों ने न केवल धरना-प्रदर्शन किया, बल्कि भानुप्रतापपुर विधायक ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस गंभीर मुद्दे को सरकार के समक्ष रखा था। बावजूद इसके, लंबे समय तक जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे रहे, जिससे मिलीभगत की आशंकाएं प्रबल हो रही थीं।

कलेक्टरों पर गाज गिरने के डर से मची खलबली

हाल ही में प्रदेश सरकार ने अवैध खनन को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी भी जिले में अवैध खदानें संचालित पाई गईं, तो सीधे तौर पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी चेतावनी के बाद जिला प्रशासन और माइनिंग विभाग हरकत में आया और आनन-फानन में यह बड़ी कार्रवाई की गई। अवैध उत्खनन में लगी 2 भारी-भरकम चेन माउंटेन मशीनें सीज की गई व रेत परिवहन में लगे 7 हाईवा वाहनों को विभाग ने अपने कब्जे में लिया। कांग्रेस के उग्र तेवरों और सरकार की सख्ती के बाद विभाग बैकफुट पर दिखा।

बड़ा सवाल: कार्रवाई या खानापूर्ति?

क्षेत्र में चर्चा है कि क्या यह कार्रवाई वाकई अवैध खनन को जड़ से खत्म करने के लिए है, या महज ऊपरी दबाव के चलते की गई एक 'खानापूर्ति' है?

ग्रामीण अब भी सशंकित हैं कि अधिकारी कुछ दिनों बाद फिर से रेत माफियाओं को खुली छूट दे सकते हैं। फिलहाल, प्रशासन की इस देर से जागी फुर्ती ने क्षेत्र के माफियाओं में हड़कंप जरूर मचा दिया है।

अशोक चक्रधारी की उपलब्धियां हैं गौरवशाली

कोंडागांव। जिला मुख्यालय से लगा हुआ ग्राम पंचायत कुम्हार पारा मृदा हस्तशिल्प जिसे टेराकोटा आर्ट भी कहा जाता है के मैजिक दिया का जादूगर अशोक चक्रधारी राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार 2006 विजेता तथा राष्ट्रीय पुरस्कार मेरिट विजेता 2016 क्षेत्र का गौरव है। स्वर्गीय डाक्टरेट जयदेव बघेल भारत सरकार द्वारा शिल्पगुरू से सम्मानित तथा पद्मश्री पंडीराम मंडावी के साथ फ्रांस तथा इटली की यात्रा कर चुके हैं। इनकी हस्तशिल्प सिद्धहस्तता से प्रभावित होकर तत्कालीन राज्यपाल महामहिम ई.एस.एल. नरसिम्हन एवं आनंदी बेन पटेल विशेष रूप से इनके गृह निवास जाकर स्वयं चाक चलाकर सम्मानित किए हैं। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न विधाओं में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिताएं आयोजित किया जाता है, जिसमें हस्तशिल्प भी एक विधा है। क्षेत्र के हस्तशिल्प इसमें भागीदारी करते हैं। विगत वर्षो से अशोक चक्रधारी भी अपनी प्रविष्ठियां प्रेषित करते रहे हैं, किंतु मेरिट प्रमाण पत्र उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। इस वर्ष 2025 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 रखी गई थी, जिसमें अशोक चक्रधारी ने बस्तर संभाग की 'कुकड़ा हाट' अर्थात 'मुर्गो की लड़ाई' को विषय वस्तु केंद्रित कर अविश्वसनीय कलाकृति तैयार कर नामांकन दाखिल किया है। उनके अनुसार इसके निर्माण में उन्हें एक माह से भी अधिक का समय लगा है। अत्यंत ही शोधकारी तथा सूक्ष्मता के कलाकृति को निर्मितकर क्षेत्र को एक अतिरिक्त राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता दिलाना सुनिश्चित कर दिया है। गौरतलब है कि अशोक चक्रधारी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए माटी कला बोर्ड के प्रथम गठन में संचालक मंडल सदस्य (वर्ष 2013-15) नामित हुए तथा छत्तीसगढ़ के कुम्हारों के विकास तथा प्रगति के लिए मैदानी स्तर पर कार्य कर उनके उत्थान का बीड़ा उठाया। पूर्व में बैंक आफ इंडिया छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा तथा अशोक चक्रधारी को छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक उनके संघर्षमय उपलब्धियों के लिए राज्य राजधानी रायपुर में सम्मान समारोह आयोजित किया है। उल्लेखनीय है, कि कोंडागांव हस्तशिल्प के राज्य पुरस्कार विजेताओं तथा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं का गढ़ है जिनमें सुखचंद पोयाम घड़वा, जयदेव बघेल, सोनाधर विश्वकर्मा, राजेन्द्र बघेल, पंचूराम सागर, तीजूराम विश्वकर्मा नामचीन हैं।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कांकेर आगमन पर आत्मीय स्वागत

कांकेर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के कांकेर आगमन पर जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया। कांकेर पहुंचने पर विधायक आशाराम नेताम सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और क्षेत्र में आगमन पर हर्ष व्यक्त किया। इस दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों की भी उपस्थिति रही। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सतत कार्य कर रही है और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है।

अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी, मॉनिटरिंग सेल, नेशनल लोक अदालत एवं हिट एंड रन के संबंध में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक हुआ सम्पन्न

कोण्डागांव। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रिगरी की अध्यक्षता एवं उनकी उपस्थिति में अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी एवं मॉनिटरिंग सेल, नेशनल लोक अदालत एवं हिट एंड रन के संबंध में बैठक मध्यस्थता कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में अपर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा, कलेक्टर कोण्डागांव नुपूर राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीमाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेशमा बैरागी पटेल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गायत्री साय, केन्द्रीय जेल जगदलपुर से कल्याण अधिकारी शिवप्रसाद करसायल, उप-जेल नारायणपुर सहायक जेल अधीक्षक पीयूष जगदाले एवं लोक अभियोजन अधिकारी तथा लोक निर्माण विभाग से सम्मलित रहे। अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटीरू- अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक के दौरान ऐसे बंदियों के मामलों पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जो लंबे समय से विचाराधीन है, जिनकी जमानत हो चुकी है परंतु वे जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अथवा जिनकी सजा की अधिकतम अवधि के सापेक्ष वे पर्याप्त समय जेल में बिता चुके हैं। न्यायाधीश महोदय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र बंदियों के मामलों में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा विधि के अनुरूप उन्हे राहत प्रदान की जाए। इसके साथ ही, बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा एवं न्याय तक उनकी सुगम पहुंच सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। साथ ही शंकर महतो के संबंध में एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित समाधान समारोह 21,22 एवं 23 अगस्त को होने वाले स्पेशल लोक अदालत के संबंध में चर्चा किया गया। मॉनिटरिंग सेल की बैठक में नवीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने की प्रक्रिया शीघ्रता से करने हेतु प्रधान न्यायाधीश महोदय द्वारा कलेक्टर कोण्डागांव को निर्देश दिए गए तथा न्यायिक अधिकारियों के निर्माणाधीन आवास गृह व न्यायिक कर्मचारियों के निर्माणधीन आवास गृह के संबंध एवं पीड़िता एवं बच्चों सहित पीड़िताओं के परिजनों के बैठक के लिए वातानुकूलित सुसजित पीड़िता एवं बच्चों के अनुकूल कक्ष शौचालय सहित बनाये जाने के संबंध में चर्चा किया गया।

पीजी कॉलेज जगदलपुर में गुरुवार को 269 परीक्षार्थी देंगे पीईटी परीक्षा, सुरक्षा के रहेंगे कड़े इंतजाम

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा आयोजित की जाने वाली पीईटी प्रवेश परीक्षा के लिए जगदलपुर के शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को केंद्र बनाया गया है, जहाँ कुल 269 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। आगामी गुरुवार 14 मई को होने वाली इस परीक्षा में इन 269 विद्यार्थियों के भविष्य का फैसला सुबह 10 बजे से दोपहर 01.15 बजे के सत्र में होगा। धरमपुरा स्थित इस केंद्र पर परीक्षार्थियों की इस संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा बैठक व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि सभी छात्र बिना किसी असुविधा के अपनी परीक्षा संपन्न कर सकें। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को समय का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि निर्धारित संख्या में पहुँच रहे इन परीक्षार्थियों की मेटल डिटेक्टर से गहन जाँच की जाएगी, जिसके लिए उन्हें परीक्षा शुरू होने से ढाई घंटे पहले केंद्र पर उपस्थित होना होगा। प्रवेश के दौरान वीक्षकों द्वारा इंटरनेट से प्राप्त मूल प्रवेश पत्र और पहचान पत्र का मिलान किया जाएगा। यदि किसी परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र में फोटो संबंधी कोई त्रुटि है, तो उसे अनिवार्य रूप से अपनी दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो साथ रखनी होगी। सभी परीक्षार्थियों के लिए सख्त ड्रेस कोड और नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है। परीक्षार्थी केवल हल्के रंग के हाफटी-शर्ट और चप्पल पहनकर ही परीक्षा हॉल में बैठ सकेंगे।

6 दिन बाद लौटी बिजली, लोगों ने ली राहत की सांस

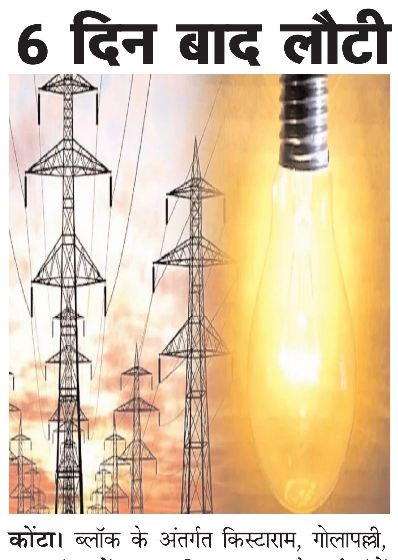

कोंटा। ब्लॉक के अंतर्गत किस्टाराम, गोलापल्ली, एलमागुंडा, सेंदूरगुड़ा सहित आसपास के कई गांवों में बीते छह दिनों से गहराया बिजली संकट आखिरकार खत्म हो गया है। लगातार छह दिन तक अंधेरे और भीषण गर्मी से जूझने के बाद क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल होने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। लंबे इंतजार के बाद घरों में पंखे, कूलर और अन्य उपकरण फिर से चालू हो पाए, वहीं मोटर चालित पेयजल व्यवस्था शुरू होने से पानी की समस्या भी कुछ हद तक कम हुई है। इससे पहले 72 घंटे से शुरू हुई समस्या छह दिन तक खिंच गई थी, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया था। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली विभाग द्वारा देर से की गई मरम्मत के चलते लोगों में नाराजगी भी देखी गई।

तकनीकी खामियां और स्टाफ की कमी बनी वजह

जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में ट्रांसफार्मरों की कम क्षमता, बढ़ते लोड और लो-वोल्टेज की समस्या पहले से ही बनी हुई है। तेमेलवाड़ा क्षेत्र में आंधी-तूफान के कारण बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसके चलते आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई थी। वहीं विभाग में स्टाफ की कमी के कारण मरम्मत कार्य में देरी हुई, जिससे समस्या लंबी खिंचती चली गई।

जनपद सदस्य स्थायी समाधान मांग की

बिजली बहाल होने के बाद क्षेत्र में भले ही राहत और खुशी का माहौल है, लेकिन कड़ती समक्का किस्टाराम जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 15 ने स्पष्ट कहा है कि ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थायी समाधान अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जगरगुड़ा कंट्रोल रूम के अंतर्गत आने वाले किस्टाराम क्षेत्र के सभी गांवों में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने, ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने और विभाग में पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करने की मांग उठाई है, ताकि भविष्य में किसी भी तकनीकी खराबी की स्थिति में त्वरित मरम्मत हो सके और लोगों को लंबे समय तक परेशानी का सामना न करना पड़े।

कबीरधाम जिले सुदूर वनांचल क्षेत्र बारहपानी गांव तक पहाड़ों के बीच पहुंची पक्की सड़क

कवर्धा। कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल और पहाड़ी क्षेत्रों में बसे गांव, जो कभी विकास की मुख्यधारा से कटे हुए थे, तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। कठिन परिस्थितियों के कारण यहां के ग्रामीणों को आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब प्रधानमंत्री जनमन योजना से इन गांवों की तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उप मुख्यमंत्री व कवर्धा विधायक विजय शर्मा के सतत प्रयासों से पहाड़ों की घाट कटिंग कर सुदूर वनांचल क्षेत्रों तक पक्की सड़कों का निर्माण किया गया है। कवर्धा विधानसभा अंतर्गत संभूपीपर से बरहापानी तक लगभग 5 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण किया गया है, जिसकी कुल लागत 3.89 करोड़ रुपए है। बारहपानी गांव, जिसकी कुल जनसंख्या 231 है, इस सड़क निर्माण के बाद अब विकास की गति प्राप्त कर रहा है। यह सड़क न केवल आवागमन का माध्यम बनी

है, बल्कि गांव के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास की आधारशिला भी साबित हो रही है। संभूपीपर से बरहापानी तक सड़क निर्माण होने से क्षेत्र के लोगों के जीवन में बदलाव आया है। पहले जहां ग्रामीणों को बरसात के दिनों में पहाड़ी पगडंडियों से गुजरना पड़ता था, वहीं अब वे आसानी से वाहनों के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे हैं। सड़क निर्माण से न केवल आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि स्थानीय स्तर पर व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है। अब किसान अपनी उपज को बाजार तक आसानी से पहुंचा पा रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। साथ ही, क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।

बरहापानी के निवासी गौतर बताते हैं कि पहले उनके गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं थी। संभूपीपर से बरहापानी तक सड़ बन जाने से वाहन पहुंचने लगे हैं और चिल्फी व कवर्धा जैसे प्रमुख स्थानों तक जाना बेहद आसान हो गया है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सड़क उनके जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आई है। अब वे भी विकास की मुख्यधारा से जुड़कर बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आया है। पीएमजीएसवाई विभाग के कार्यपालन अभियंता एस.के. ठाकुर ने बताया कि इस प्रकार के कार्यों का उद्देश्य सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ना है, ताकि वहां के निवासियों को सुविधाएं मिल सकें। प्रधानमंत्री जनमन योजना और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से आज कबीरधाम के वनांचल क्षेत्रों में विकास की नई राह खुल रही है।

बंगाल, असम, पुडुचेरी जीतने पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को दी बधाई

बेमेतरा। पश्चिम बंगाल, असम एवं पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए को मिली ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व विजय पर रायपुर शहर जिला भाजपा प्रभारी एवं पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा बेमेतरा राजेन्द्र शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष भाजपा किरण देव से सौजन्य भेंट कर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह विजय केवल चुनावी सफलता नहीं, बल्कि देश की जनता के अटूट विश्वास, समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और मजबूत संगठन की जीत है। राजेन्द्र शर्मा ने इस ऐतिहासिक जीत पर सभी कार्यकर्ता साथियों को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता ने दिन-रात मेहनत कर संगठन को मजबूत किया और जनता तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यह परिणाम भाजपा की विचारधारा, राष्ट्र प्रथम की नीति और सेवा भाव से प्रेरित राजनीति की जीत है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसका सीधा प्रभाव इन चुनाव परिणामों में स्पष्ट रूप से देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है और देश की जनता ने एक बार फिर विकास की राजनीति पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। राजेन्द्र शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार की योजनाएं–गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, किसान हित, युवा रोजगार एवं बुनियादी ढांचे के विकास–जन-जन तक पहुंच रही हैं, जिससे जनता का भरोसा लगातार बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम एवं पुडुचेरी में मिली यह जीत भाजपा के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है और आने वाले समय में संगठन और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की मेहनत से बंगाल में ऐतिहासिक परिणाम आया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में संगठन को नई दिशा और ऊर्जा मिल रही है। साथ ही उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के समर्पण को इस विजय का प्रमुख आधार बताया। अंत में राजेन्द्र शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा और एनडीए आने वाले समय में भी जनसेवा, सुशासन और विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रहकर देश और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे तथा जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरेंगे।

चरडोंगरी में 'कागज़ी दो दीवार' का खेलः 7.88 लाख की योजना में एक ही वाल खड़ा कर पूरा भुगतान

कवर्धा। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत ग्राम पंचायत चरडोंगरी में स्वीकृत ताली (नाली) निर्माण कार्य अब गंभीर सवालों के घेरे में है। वर्ष 2024-25 के लिए 7.88 लाख रुपये की स्वीकृति के साथ 07-06-2025 से 13-08-2025 के बीच कार्य पूर्ण दर्शाया गया है। कार्य एजेंसी के रूप में सरपंच, ग्राम पंचायत चरडोंगरी तथा जनपद पंचायत कवर्धा का नाम दर्ज है। लेकिन स्थल की स्थिति और सूचना के अधिकार से प्राप्त दस्तावेजों ने निर्माण और भुगतान प्रक्रिया पर गंभीर आपत्तियां सामने रख दी हैं। उक्त नाली निर्माण कार्य सुकदेव के घर से भोगेश्वर के घर तक, तालाब किनारे कराया गया है। स्थल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जहां दो साइड वॉल (दीवार) प्रस्तावित थीं, वहां केवल एक साइड वॉल का निर्माण किया गया है। दूसरी ओर तालाब में निर्मित रिटर्निंग वॉल को नाली की दूसरी दीवार के रूप में समाहित कर भुगतान आहरित कर लिया गया। तकनीकी दृष्टि से यह दो अलग प्रकृति के कार्य हैं, जिन्हें एक ही मद में जोड़ना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। सूचना के अधिकार से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार, नाली के एक वाल का निर्माण कर दोनों वाल का मूल्यांकन और सत्यापन दर्शाते हुए पूर्ण राशि आहरण कर ली गई। माप पुस्तिका (एमबी) में दो दीवारों का उल्लेख किया गया है, जबकि भौतिक स्थिति अलग संकेत देती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मापन, सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही अथवा मिलीभगत की आशंका बनती है। जनपद स्तर पर तकनीकी परीक्षण और भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यह पूरा मामला इसलिए और संवेदनशील हो जाता है क्योंकि यह क्षेत्र प्रदेश के पंचायत मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे क्षेत्र में विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और वित्तीय अनुशासन की अपेक्षा और अधिक रहती है। यदि जमीनी स्तर पर इस प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो यह शासन की साख और निगरानी व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 तथा शासकीय वित्तीय नियमों के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य का भुगतान केवल वास्तविक, मापित और प्रमाणित कार्य के आधार पर किया जा सकता है। लोक निर्माण विभाग के तकनीकी मानकों के तहत नाली निर्माण में दोनों साइड वॉल का होना आवश्यक होता है, जिससे संरचना सुरक्षित और टिकाऊ रहे। एक दीवार के स्थान पर तालाब की रिटर्निंग वॉल को जोड़कर भुगतान लेना नियमानुकूल नहीं माना जा सकता। यदि दस्तावेजों में वास्तविकता से भिन्न प्रविष्टि की गई है, तो यह गंभीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण बनता है। ग्रामीणों और जागरूक नागरिकों ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। उनका कहना है कि कागजों में दर्ज निर्माण और धरातल पर मौजूद कार्य के बीच अंतर की तकनीकी जांच कराई जाए तथा दोषियों के विरुद्ध वसूली और दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिला स्तर पर एक स्वतंत्र जांच टीम गठित करने की मांग तेज हो गई है। मांग की जा रही है कि जिला प्रशासन, जिला पंचायत और तकनीकी विशेषज्ञों की संयुक्त टीम बनाकर स्थल निरीक्षण, माप पुस्तिका का सत्यापन, स्वीकृत एस्टीमेट का मिलान तथा भुगतान अभिलेखों की ऑडिट जांच कराई जाए। जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सके। अब प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी नजर टिकी है। 7.88 लाख की इस परियोजना का वास्तविक मूल्यांकन और जिम्मेदारी तय होना आवश्यक है, ताकि जनहित की राशि का दुरुपयोग न हो और विकास कार्यों में विश्वास कायम रह सके।

एथेनाल विस्थापन आंदोलन की उम्र दराज महिलाएं आज भी प्रताड़ना झेलने मजबूर हैं

बेमेतरा। एथेनाल विस्थापन आंदोलन की उम्र दराज महिलाएं प्रताड़ना झेलने मजबूर हैं यह जानकारी देते हुए संतोष साहू, खेमराम साहू, दौना यादव, अजिताभ मिश्रा,नरेश साहू, सिद्दीक खान,चंदन साहू,गायत्री जोगी ने बताया कि इस ज़माने में गलत को गलत कहना ही गलत है.इन लोगों ने बताया कि पथर्रा रांका में एथेनाल प्लांट के विरोध की अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करने करवाकर बायोटेक एथेनाल प्लांट मालिक आज भी निर्बाध गति से धुंआ, बदबू और गंदा पानी उगल रहा है।इसका विरोध को पुलिस प्रशासन के दम पर दमन करके बायो टेक फ्यूल्स को खुली छूट दी जा चुकी है।गांव को प्रदूषण से बचाने, भारत के संविधान की धारा 21, जीने के अधिकार के तहत शांति पूर्ण विरोध करने वालों को सबक सिखाने, थोक के भाव से एफआईआर दर्ज की गई थी। अब प्लांट के आतंक को अपनी नियति मान कर चुप बैठ गए ग्रामीणों पर पुराने केस खोल कर एक बार पुनः कार्यवाही की जा रही है।

महंगाई के खिलाफ गैस सिलेंडर की शव यात्रा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में भव्य प्रदर्शन

बेमेतरा। बढ़ती महंगाई एवं घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में लगातार वृद्धि के विरोध में बेमेतरा जिला मुख्यालय में व्यापक एवं प्रभावी प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में शहर के सिग्नल चौक पर गैस सिलेंडर की प्रतीकात्मक अर्थी बनाकर उसकी शव यात्रा निकाली गई, जो आमजन के आक्रोश का प्रतीक बनी कांग्रेसजनों ने कहा कि गैस सिलेंडर के लगातार बढ़ते दामों के कारण शादियों–विवाह, घरेलू उपयोग तथा सार्वजनिक आयोजनों में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे गरीब एवं मध्यम वर्ग का जीवन अत्यंत प्रभावित हुआ है। इसी जनहित के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरकर जनता की आवाज बुलंद कर रही है। शव यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सिग्नल चौक पहुंची, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन केवल एक विरोध नहीं, बल्कि आम जनता के हक और राहत के लिए उठाया गया मजबूत कदम है। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी सहित कांग्रेस के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से कविता साहू मंगत साहू अध्यक्ष जिला युवा कांग्रेस प्रांजल तिवारी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला साहू, शहर ब्लॉक अध्यक्ष रश्मि मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य शशी प्रभा गायकवाड़, सुशीला जोशी, योगिता साहू, रूबी सलूजा, जनता साहू, नेमा निषाद, नीलम टंडन, बाल कुमारी (जिला पंचायत सदस्य), हेमिन यादव, मिथलेश वर्मा (ब्लॉक अध्यक्ष), झम्मन बघेल रवि रजक सीताराम यदु, मनोज शर्मा, भीखम साहू, वतन मिश्रा, दीपक दिनकर, संतोष पटेल, राजेन्द्र दुबे, बहल राम वर्मा, बलवंत साहू, मिंटा नामदेव, राम ठाकुर, हरि साहू, शिव वर्मा, हेमू साहू, मिथलेश वर्मा, संजय वर्मा, भाव सिंह राज बोधन साहू धनंजय साहू मोहित वर्मा प्रकाश साहू सरपंच जेवरी चंदू शितलानी, बहल वर्मा सोहित भीखम साहू संजय वर्मा, यासिफ खान, वाहिद रवानी, गुड्डु सेन एवं गोविंदा राजपूत शुभम सोनी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे। अंत में कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि महंगाई पर शीघ्र नियंत्रण नहीं किया गया।

धनेली (बीही बारी) में मनरेगा कार्य ठप, फिर भी जारी मस्टरोल, कार्यक्रम अधिकारी की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न

कवर्धा। ग्राम पंचायत गांगी बहरा जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा अंतर्गत धनेली स्थित बीही बारी के पास मनरेगा के तहत स्वीकृत पुलिया निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। सूचना पट्ट के अनुसार कार्य प्रारंभ तिथि 14 मई 2025 है, किंतु पिछले लगभग 15 दिनों से स्थल पर निर्माण पूरी तरह बंद बताया जा रहा है।

इसके बावजूद मस्टरोल जारी होने और उपस्थिति दर्ज किए जाने की जानकारी ने प्रशासनिक जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। यह स्थिति महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के मूल प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होती है। अधिनियम के तहत मजदूरी केवल वास्तविक कार्य के आधार पर देय है तथा कार्यस्थल पर पारदर्शिता, सूचना प्रदर्शन और सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य है। यदि कार्यस्थल पर गतिविधि शून्य है, तो मस्टरोल में दर्ज उपस्थिति नियमों का प्रत्यक्ष उल्लंघन मानी जाएगी। मनरेगा संचालन दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी पर कार्यों की निगरानी, मस्टरोल सत्यापन और भुगतान पूर्व भौतिक निरीक्षण की स्पष्ट जिम्मेदारी निर्धारित है। ऐसे में कार्य बंद रहने के बावजूद मस्टरोल जारी होना प्रशासनिक लापरवाही या संभावित वित्तीय अनियमितता की ओर संकेत करता है। यदि बिना कार्य के मजदूरी का भुगतान हुआ है या प्रक्रिया प्रचलित है, तो यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग) एवं धारा 318 (धोखाधड़ी) के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ सकता है।

सेवानिवृत्त दो शिक्षकों को दी गई सम्मान बिदाई

बेमेतरा। बेमेतरा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम कन्या विद्यालय बेमेतरा में व्याख्याता द्वय दुर्गा राम साहू एवं योगेन्द्र वर्मा के सेवानिवृत्ति पर विद्यालय परिवार द्वारा बिदाई समारोह का आयोजन किया गया। उक्त दोनों व्याख्याताओं ने फरवरी में अपनी अधिवार्षिकी पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए। जिनके सम्मान में शिक्षा सत्र के अंतिम दिवस बिदाई समारोह का आयोजन किया गया। दोनों सेवानिवृत्त व्याख्याताओं के मुख्य आतिथ्य में एवं प्राचार्य कविता बाचपेयी की अध्यक्षता कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम प्रमोद ठाकुर ने दोनों के नाम के अनुरूप कार्य व व्यवहार का सटीक विश्लेषण करते हुए दोनों के स्वस्थ एवं सुखी जीवन की कामना की। एस एन अली ने साथ बिताए यादों को स्मरण करते हुए स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दिए। हिरेंद्र साहू एवं आराधना जोसेफने भी दोनों के कार्यशैली एवं व्यवहार को अनुकरणीय बताया। प्रधान पाठक रामेश्वर प्रसाद बंजारे ने सरल व बेदाग सेवाकाल के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दिए। प्राचार्य ने दोनों व्याख्याताओं के सरलता, समय व कार्य के प्रति सजगता की प्रशंसा करते हुए विद्यालय परिवार की ओर से सुखद एवं खुशनुमा जीवन की शुभकामनाएं दी। योगेन्द्र वर्मा ने अपने 43 वर्षों की सेवा के विशेष लम्हों को याद करते हुए कहा कि हमारा सौभाग्य है हम ऐसे नौनिहालों जिज्ञासुओं के बीच रहते हैं जिससे हमें सतत् सक्रिय और नई जानकारियां प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने सभी से मिले सहयोग और अपनत्व के लिए आभार व्यक्त किया।

कांग्रेस ने किया डोंगरगांव थाना का घेराव, ग्रामीण पदाधिकारी से अभद्रता के आरोप

अवैध शराब बिक्री की शिकायत से जुड़ा है मामला

डोंगरगांव नगर। अवैध शराब बिक्री की शिकायतों के मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने डोंगरगांव थाना का घेराव कर दिया। कांग्रेसजनों ने कांग्रेस के ग्रामीण पदाधिकारी द्वारा पुलिस से अवैध शराब बिक्री की शिकायत करने पर पुलिस द्वारा दबावपूर्वक एवं अभद्र पूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया। हालांकि कांग्रेस संगठन ने एकजुटता दिखाते हुए घेराव कर दिया। अंततः 2 घंटे की बहस के बाद पुलिस द्वारा खेद जताने से माजरा खत्म होने की खबर है। कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने मीडिया को अधिकारिक तौर पर बताया कि क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री की शिकायत को लेकर कांग्रेस के मारगांव क्षेत्र के पदाधिकारी एवं जनपद सदस्य के पति लीलेश पटेल ने पुलिस को कुछ दिनों पुर्व ही अवैध शराब की सूचना दी थी। इस पर पुलिस कार्रवाई को लेकर असंतोष जताया गया। कांग्रेसजनों की माने तो इसी दौरान थाना में पदस्थ प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी ने संबंधित जनप्रतिनिधि पर शराब पीकर बात करने की टिप्पणी कर दी। इस बातचीत से विवाद बढ़ गया। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दूसरे दिन दबावपूर्वक लीलेश को थाने बुलाकर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसकी जानकारी लिलेश ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष को देने के बाद स्वयं ब्लॉक अध्यक्ष टिकेश साहू कुछ प्रमुख पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ थाना में धमक पड़े। उपरांत बड़ी संख्या में नगर व ग्रामीण क्षेत्र के कांग्रेसी थाने पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। घेराव के दौरान कार्यकर्ताओं ने थाने की अव्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जताई। टीआई कक्ष में बैठकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। अंततः आईपीएस आदित्य कुमार द्वारा घटनाक्रम को लेकर खेद जताने के बाद माजरा शांत हो गया। हालांकि इस मामले में आईपीएस आदित्य कुमार ने किसी भी प्रकार के विवाद से इनकार किया है। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष टिकेश साहू के अलावा संजय मुतकुरे, रोशन यदु, मोहनीश साहू, चुम्मन साहू, सुंदर साहू, देवेंद्र साहू, मयंक यदु, महेश साहू, गोपाल टावरी, अखिलेश नखत, प्रियंक जैन, रितेश राजपूत, टिंकू देवांगन, पुष्पेन्द्र नेताम, लोकेन्द्र राजपूत, सतेश्वर पटेल, राकेश देवांगन, रोमन पटेल, अशोक साहू, भावेश श्रीवास्तव, अब्दुल खान, अमित ठाकुर सहित विभिन्न मंडलों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सांसद संतोष पाण्डेय की अनुशंसा पर विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 9.98 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति

कवर्धा। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पाण्डेय की अनुशंसा पर कलेक्टर गोपाल वर्मा द्वारा कवर्धा और सहसपुर लोहारा विकासखंड के अलग-अलग ग्रामों में निर्माण कार्या के लिए 9 लाख 98 हजार 700 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। निर्माण कार्य के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद कवर्धा, सहसपुर लोहारा को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है। सांसद संतोष पाण्डेय की अनुशंसा से ग्राम पंचायत लखनपुर कला में भवन निर्माण कार्य सरस्वती शिशु मंदिर के पास के लिए 4 लाख 99 हजार 900 रूपए, रामजानकी मंदिर के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण के लिए 1 लाख 99 हजार 200 रूपए और ग्राम पंचायत गौरमाटी में मंदिर के साम्ने कांक्रीटीकरण कार्य के लिए 3 लाख 99 हजार 700 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अनुशंसा पर विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 19.50 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति

कवर्धा। उपमुख्यमंत्री व कवर्धा विधायक विजय शर्मा की अनुशंसा पर कलेक्टर गोपाल वर्मा द्वारा कवर्धा विधानसभा के अलग-अलग ग्रामों में निर्माण कार्या के लिए 19 लाख 50 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। निर्माण कार्य के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी कवर्धा को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है। उपमुख्यमंत्री व कवर्धा विधायक विजय शर्मा की अनुशंसा से कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के कवर्धा शहर के वार्ड क्रमांक 16 मां दंतेश्वरी वार्ड में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रूपए और वार्ड 13/14 में महर्षि कश्यप चैक निर्माण के लिए 9 लाख 75 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है।

संपादकीय

कहीं सत्ता पलटी, कहीं भरोसा बरकरार, बदल रहा है जनता का राजनीतिक मूड

कहा जा सकता है कि इन चुनावों में भाजपा ने जहां पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में जीत हासिल कर अपनी उपस्थिति साबित की है, वहीं कांग्रेस भी केरल की जीत को अपनी बड़ी उपलब्धि बता सकती है।चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के जैसे नतीजे सामने आए हैं, उनसे साफ है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जहां मतदाताओं ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया, वहीं असम और पुडुचेरी में लोगों ने मौजूदा सरकार पर भरोसा कायम रखा। इसमें चौंकाने वाले नतीजे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से आए, जहां चुनाव प्रचार के क्रम में बहुस्तरीय उतार-चढ़ाव के बावजूद लोगों के लिए यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि सत्ताधारी पार्टियों का प्रदर्शन बेहद कमजोर हो सकता है। इन राज्यों में इतने बड़े उलटफेर की उम्मीद कम ही लोगों ने की थी।दरअसल, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार के प्रति दिखने वाला जनसमर्थन चुनाव और मतदान के मोर्चे पर उलट नतीजे देने वाला साबित हुआ। हालांकि राज्य में भाजपा ने जीत के लिए जिस स्तर पर जाकर मेहनत की, मतदाताओं के वोट अपने पक्ष में लाने के लिए एक व्यापक रणनीतिक राजनीति पर काम किया और यहां तक भावनात्मक मुद्दों का भी सहारा लिया, उसका साफ असर मतगणना और नतीजों पर दिखा। जाहिर है, लंबे समय के बाद अब पश्चिम बंगाल एक और सत्ता परिवर्तन का गवाह बन रहा है, जहां विचारधाराओं का सफर क्रमशः बदलता दिखा है।वहीं तमिलनाडु में एमके स्टालिन के नेतृत्व वाले द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) को लेकर बहुत कम लोगों ने यह अंदाजा लगाया होगा कि चुनाव के परिणाम में उसकी स्थिति इस कदर खराब रहेगी। गौरतलब है कि फिल्मों की दुनिया से तमिलनाडु की राजनीति में आकर हाल के वर्षों में उभरे और अपने प्रशंसकों के बीच थलापति के नाम से मशहूर जोसेफ विजय ने अपने पहले ही चुनाव में राज्य की राजनीति में बीते कुछ सालों से एकछत्र राज करने वाले नेता एमके स्टालिन और उनकी पार्टी द्रमुक को करारी शिकस्त दी। अब तमिलनाडु द्रमुक और अन्नाद्रमुक के इर्द-गिर्द घूमने वाली राजनीति के समांतर एक नए दौर में प्रवेश कर गया है। यह देखने की बात होगी कि आने वाले वर्षों में यह राज्य किस राजनीतिक धारा का केंद्र बनेगा।जहां तक केरल का सवाल है, तो वहां आमतौर पर वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड लोकतांत्रिक मोर्चे के बीच सत्ता में फेरबदल होता रहा है। इस लिहाज से देखें तो दो कार्यकाल के बाद वामपंथी मोर्चा सत्ता से बाहर हुआ है और अच्छी उपस्थिति के साथ कांग्रेस को महत्त्वपूर्ण जीत मिली है।इसके अलावा, असम में एक तरह से अपेक्षित नतीजे आए हैं, जहां भाजपा ने फिर से भारी जीत हासिल की है। यह तब भी संभव हुआ, जब राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के रुख को लेकर कई तरह के विवाद चुनाव प्रचार के केंद्र में रहे। इसी तरह, केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी के परिणामों के मुताबिक, वहां सत्तारूढ़ राजग गठबंधन ने एक बार फिर बहुमत हासिल कर अपनी सत्ता कायम रखी।कहा जा सकता है कि इन चुनावों में भाजपा ने जहां पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में जीत हासिल कर अपनी उपस्थिति साबित की है, वहीं कांग्रेस भी केरल की जीत को अपनी बड़ी उपलब्धि बता सकती है।

हादसे का इंतजार नहीं कर सकती सरकार, परस्पर पूरक हैं धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हाईकोर्ट के दो हालिया फैसले

दूसरे फैसले में अदालत ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर सबका समान अधिकार है, और निजी स्थल पर भी धार्मिक स्वतंत्रता असीमित नहीं है। यदि कोई गतिविधि सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने लगे तो उसे नियंत्रित करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। सरकार लोक व्यवस्था के छिन्न-भिन्न होने का इंतजार नहीं कर सकती। ये दोनों फैसले विरोधाभासी नहीं हैं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं और मिलकर उस व्यवस्था को रेखांकित करते हैं जिसके भीतर एक लोकतांत्रिक, बहुलवादी समाज में धर्म और कानून को साथ-साथ चलना होता है। इस न्यायिक दृष्टिकोण ने इस मूल सिद्धांत को रेखांकित किया है कि किसी भी नागरिक या समूह का अधिकार तभी तक सुरक्षित है, जब तक वह दूसरे नागरिकों के अधिकारों, सार्वजनिक व्यवस्था और सामूहिक हितों से टकराव नहीं पैदा करता।

(रितिका सिंह सिसोदिया)

एक माह के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो फैसले, दो अलग-अलग समय में आए, लेकिन दोनों को मिलाकर पढ़ें तो एक स्पष्ट और संतुलित संवैधानिक दर्शन उभरकर सामने आता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उसमें अधिकार भी हैं और उन अधिकारों की सीमाएं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। एक माह के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो फैसले, दो अलग-अलग समय में आए, लेकिन दोनों को मिलाकर पढ़ें तो एक स्पष्ट और संतुलित संवैधानिक दर्शन उभरकर सामने आता है।

पहले फैसले में अदालत ने कहा था कि नमाजियों की संख्या सीमित करना गलत है, कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

दूसरे फैसले में अदालत ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर सबका समान अधिकार है, और निजी स्थल पर भी धार्मिक स्वतंत्रता असीमित नहीं है। यदि कोई गतिविधि सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने लगे तो उसे नियंत्रित करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। सरकार लोक व्यवस्था के छिन्न-भिन्न होने का इंतजार नहीं कर सकती। ये दोनों फैसले विरोधाभासी नहीं हैं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं और मिलकर उस व्यवस्था को रेखांकित करते हैं जिसके भीतर एक लोकतांत्रिक, बहुलवादी समाज में धर्म और कानून को साथ-साथ चलना होता है।

इस न्यायिक दृष्टिकोण ने इस मूल सिद्धांत को रेखांकित किया है कि किसी भी नागरिक या समूह का अधिकार तभी तक सुरक्षित है, जब तक वह दूसरे नागरिकों के अधिकारों, सार्वजनिक व्यवस्था और सामूहिक हितों से टकराव नहीं पैदा करता। यह केवल एक कानूनी व्याख्या नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक चेतना का संकेत है, जो यह बताता है कि आधुनिक राज्य व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक हितों के बीच संतुलन बनाकर ही चल सकती है।

सबसे पहले संभल के मूल विवाद को समझते हैं। यह विवाद एक ऐसी भूमि से संबंधित है जिसे याचिकाकर्ता अपनी निजी भूमि बताता है और उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वहां नमाज अदा करने के लिए परमादेश जारी करने की मांग की थी। प्रारंभ में जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया था कि एक विशेष परिसर में नमाजियों की संख्या को सीमित किया जाए। आधार यह था कि भीड़ बढ़ने से कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। यह प्रशासनिक दृष्टिकोण एहतियात और व्यवस्था बनाए रखने की भावना से प्रेरित था, लेकिन इस आदेश को चुनौती देते हुए मामला न्यायालय तक पहुंचा।

न्यायपालिका ने अपने पहले निर्णय में कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य का मूल दायित्व है। न्यायालय के उस आदेश का भावार्थ यह था कि यदि प्रशासन यह मान ले कि किसी धार्मिक गतिविधि के कारण स्वाभाविक रूप से व्यवस्था बिगड़ सकती है, और उसी आधार पर प्रतिबंधात्मक कदम उठाए जाएं, तो यह दृष्टिकोण संविधान की भावना के विपरीत होगा।

लेकिन इस पूरे विवाद का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसे बाद में न्यायालय के एक अन्य निर्णय में अधिक स्पष्टता के साथ सामने रखा गया। इस दूसरे दृष्टिकोण ने सार्वजनिक भूमि, निजी संपत्ति और धार्मिक गतिविधियों के बीच संतुलन की संवैधानिक सीमा को विस्तार से समझाया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी अधिकार की रक्षा तभी तक की जा सकती है, जब तक वह सार्वजनिक हित और अन्य नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता।इस संदर्भ में न्यायालय ने निजी और सार्वजनिक गतिविधियों के बीच अंतर को अत्यंत स्पष्ट शब्दों में रखा है कि निजी प्रार्थना, पारिवारिक पूजा, और ऐसी सीमित भक्ति गतिविधि जो वास्तव में परिसर के लिए आंतरिक रहती है, सामान्यतः अनुच्छेद 25 और 26 के संरक्षित क्षेत्र में आती है। यह पंक्ति इस बात की पुष्टि करती

है कि संविधान व्यक्ति की आस्था और निजी जीवन की स्वतंत्रता को पूर्ण संरक्षण देता है, लेकिन इस संरक्षण की एक सीमा भी है। यह केवल तब तक लागू है जब तक गतिविधि वास्तव में निजी और सीमित बनी रहती है।

संभल विवाद के संदर्भ में यही प्रश्न केंद्रीय था कि क्या किसी निजी या सीमित स्थान पर होने वाली गतिविधि धीरे-धीरे सार्वजनिक स्वरूप ग्रहण कर रही थी?

न्यायालय ने इस पहलू को अत्यंत व्यावहारिक दृष्टि से देखा और कहा कि जैसे ही कोई गतिविधि 'सामूहिक चरित्र' ग्रहण करती है, वह केवल आंतरिक आस्था का विषय नहीं रह जाती।

अदालत के शब्दों में, 'एक बार जब गतिविधि ऐसा सामूहिक चरित्र ग्रहण कर लेती है, तो यह केवल आंतरिक आस्था का मामला नहीं रह जाता।' इस परिवर्तन के साथ ही उसके प्रभाव भी व्यापक हो जाते हैं। प्रवेश और निकास से लेकर यातायात और पार्किंग संबंधी चिंताएं पैदा हो सकती है, इलाके का चरित्र बदल सकता है, शोर उत्पन्न हो सकता है, पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता हो सकती है और संवेदनशील क्षेत्रों में, अंतर-समुदाय तनाव की आशंका पैदा कर सकती है।

ऐसी स्थिति में गतिविधि 'एक सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक आयाम ग्रहण कर लेती है।' यहां यह भी देखना होगा कि प्रकरण ऐसे जिले का है जो कुछ समय पहले सांप्रदायिक विमर्श के केंद्र में था, जहां धार्मिक तनाव की आग भड़क चुकी है और सड़कों पर खून बह चुका है। कोर्ट की अवधारणा स्पष्ट है कि अधिकार केवल घोषित नहीं होते, उनका प्रभाव भी उनकी प्रकृति निर्धारित करता है। यदि प्रभाव सार्वजनिक हो जाता है, तो वह भी सार्वजनिक नियमन के दायरे में आ जाता है।

संभल मामले के पहले निर्णय और इसके बाद के विस्तृत निर्णय को साथ रखकर देखने पर एक स्पष्ट तस्वीर उभरती है। पहले निर्णय में प्रशासनिक हस्तक्षेप पर प्रश्न उठाया गया, जबकि दूसरे निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि अनियंत्रित विस्तार भी संवैधानिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। यह दोनों दृष्टिकोण मिलकर यह स्थापित करते हैं कि न तो अति-प्रतिबंध उचित है और न ही असीमित विस्तार। निर्णय में कहा गया कि 'ऐसा नहीं है कि निजी संपत्ति सभी संरक्षण खो देती है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था के प्रभावित होने की स्थिति में ऐसी संपत्ति का उपयोग विशुद्ध रूप से निजी नहीं रह जाता और उचित विनियमन के अधीन हो जाता है।'

यह कथन शासन और प्रशासन के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि अधिकारों का उपयोग सामाजिक प्रभाव से अलग नहीं देखा जा सकता। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में शासन-प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रशासन का दायित्व केवल कानून लागू करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि किसी भी गतिविधि से समाज में असंतुलन न पैदा हो। यही कारण है कि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई गतिविधि कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने की संभावना रखती है, तो राज्य को हस्तक्षेप का पूरा अधिकार है।

संभल का यह विवाद अंततः हमें एक व्यापक सिद्धांत की ओर ले जाता है कि लोकतंत्र केवल अधिकारों का संग्रह नहीं है, बल्कि संतुलित जिम्मेदारियों का ढांचा है। यह ढांचा तभी मजबूत रहता है जब प्रत्येक अधिकार अपने दायरे में सीमित रहे और किसी दूसरे के अधिकार को प्रभावित न करे। यही संतुलन संभल विवाद को केवल एक स्थानीय मुद्दे से ऊपर उठाकर एक व्यापक संवैधानिक और सामाजिक विमर्श में बदल देता है और यही इस पूरे प्रसंग का सबसे स्थायी संदेश है कि विधि का शासन तभी जीवित रहता है जब अधिकार, कर्तव्य और प्रशासनिक विवेक एक साथ संतुलित रूप में कार्य करें।

श्यामा बाबू के संकल्प की जीत, विवेकानंद के विचारों की प्रीति- बंगाल में राष्ट्रवाद का नया सूर्योदय

(भारत भूषण अरजरिया)

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनसंघ के प्रणेता थे, उनके विचारों की प्रासंगिकता आज बंगाल की इस ऐतिहासिक जीत में साफ झलकती है। उन्होंने उस समय बंगाल के विभाजन के संकट को समझा था और यह सुनिश्चित किया था कि बंगाल का एक हिस्सा भारतीय संस्कृति और अस्मिता के साथ सुरक्षित रहे।

बंगाल केवल एक भौगोलिक भूभाग नहीं है, बल्कि यह वह विचार है जिसने आधुनिक भारत की आधारशिला रखी। आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाला है, क्योंकि यह मात्र एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि उस माटी की अपनी जड़ों की ओर वापसी है, जिसने कभी %वंदे मातरम्% के उद्घोष से पूरे आर्यावर्त को जगाया था। यह जीत उस संकल्प की सिद्धि है जो दशकों से बंगाल की गलियों में मौन था, किंतु मरा नहीं था। आज जब बंगाल में राष्ट्रवाद का भगवा ध्वज लहरा रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि गंगासागर की लहरें डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उन बलिदानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं, जिन्होंने एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। यह उस विचारधारा की विजय है जो मानती है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही भारत की नियति है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनसंघ के प्रणेता थे, उनके विचारों की प्रासंगिकता आज बंगाल की इस ऐतिहासिक जीत में साफ झलकती है। उन्होंने उस समय बंगाल के विभाजन के संकट को समझा था और यह सुनिश्चित किया था कि बंगाल का एक हिस्सा भारतीय संस्कृति और अस्मिता के साथ सुरक्षित रहे। आज उनकी आत्मा निश्चित रूप से तृप्त हो रही होगी, क्योंकि जिस बंगाल को वैचारिक शून्यता और तुष्टीकरण की राजनीति ने जकड़ लिया था, उसने अब अपने सबसे प्रतापी पुत्र के सपनों को साकार करने का मार्ग चुन लिया है। यह जीत बताती है कि समय कितना भी क्यों न बदल जाए, सत्य और राष्ट्रवाद की धारा कभी सूखती नहीं है; वह बस सही समय की प्रतीक्षा करती है। बंगाल ने आज यह सिद्ध कर दिया है कि वह अपनी गौरवशाली विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए तत्पर है। इस परिवर्तन की गहराई को समझने के लिए हमें स्वामी विवेकानंद के उन संदेशों को स्मरण करना होगा, जिन्होंने विश्व पटल पर भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता को स्थापित किया था। संघ और उससे प्रेरित सभी समवैचारिक संगठनों के लिए विवेकानंद केवल एक पथ-प्रदर्शक नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद के जीवंत प्रतीक हैं। उन्होंने कहा था कि 'उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।' बंगाल की जनता ने आज उसी मंत्र को आत्मसात किया है। दशकों की राजनीतिक हिंसा, वैचारिक दमन और सांस्कृतिक विस्मृति के बाद, बंगाल की चेतना जागृत हुई है। यह उस 'सिंह-गर्जना' की गूंज है जिसने कभी शिकागो के मंच से दुनिया को हिला दिया था। आज विवेकानंद की उस कर्मठता और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की विजय हुई है, जो समावेशी भी है और अजेय भी।

गंगोत्री से गंगासागर तक शुरू हुई यह संकल्प यात्रा अब अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। जिस प्रकार गंगा नदी हिमालय की दुर्गम चोटियों को चीरते हुए मैदानों को सींचती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर सागर से एकाकार हो जाती है, उसी प्रकार राष्ट्रवाद की यह लहर उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए आज बंगाल के हृदय में समा गई है। यह यात्रा केवल सत्ता के परिवर्तन की नहीं, बल्कि व्यवस्था के परिवर्तन और विचारों के शुद्धिकरण की यात्रा है। 'वंदे मातरम्' के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जिस भारत माता की कल्पना की थी, वह सुजलाम-सुफलाम होने के साथ-साथ शक्तिस्वरूपा भी थी। आज बंगाल ने उसी शक्ति की आराधना की है और दिखा दिया है कि माँ भारती के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बंगाल के इस ऐतिहासिक जनादेश के पीछे उन अनगिनत कार्यकर्ताओं का लहू और पसीना है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्रवाद का दीप जलाए रखा। यह उन बलिदानियों को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपनी आँखों में 'सोनार बांग्ला' का सपना संजोया था–एक ऐसा बंगाल जो सांप्रदायिकता से मुक्त हो, जहाँ विकास की धारा अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और जहाँ दुर्गा पूजा का शंखनाद बिना किसी भय के सुनाई दे। आज की यह जीत बंगाल की उस महान परंपरा का सम्मान है जिसमें चैतन्य महाप्रभु की भक्ति, सुभाष चंद्र बोस का शौर्य और रवींद्रनाथ टैगोर की लेखनी का प्रभाव समाहित है। यह जीत घोषणा करती है कि बंगाल अब केवल पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, बल्कि नए भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगा। यह ऐतिहासिक दिन इस विश्वास को सुदृढ़ करता है कि विचारधारा की जड़ें यदि सत्य में हों, तो उसे कोई भी दमनकारी शक्ति मिटा नहीं सकती।

पश्चिम बंगाल में भाजपा की चली सुनामी के सियासी मायने दूरगामी महत्व वाले

केंद्र में विगत बारह वर्षों से सत्तारूढ़ 'भारतीय जनता पार्टी' ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में निर्णायक जीत दर्ज करके जनसंघ के संस्थापक और बंगाल मूल के दूरदर्शी हिंदूवादी राजनेता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अद्भुत श्रद्धांजलि दी है। सच कहूं तो आरएसएस के इस सुप्रसिद्ध सिपाही का कश्मीर में दिया हुआ सियासी बलिदान व्यर्थ नहीं गया। खासकर यह उपलब्धि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर भाजपा द्वारा उसे दिया हुआ बहुमूल्य वैचारिक तोहफा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत केवल सरकार बदलने की घटना नहीं होगी, बल्कि यह भारतीय राजनीति में 'पूर्वी भारत के वैचारिक परिवर्तन' का प्रतीक मानी जाएगी।

(कमलेश पांडे)

पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत केवल सरकार बदलने की घटना नहीं होगी, बल्कि यह भारतीय राजनीति में 'पूर्वी भारत के वैचारिक परिवर्तन' का प्रतीक मानी जाएगी। इससे विपक्ष का शक्ति-संतुलन बदलेगा, भाजपा का राष्ट्रीय आत्मविश्वास बढ़ेगा और बंगाल की दशकों पुरानी राजनीतिक संस्कृति में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है।

केंद्र में विगत बारह वर्षों से सत्तारूढ़ 'भारतीय जनता पार्टी' ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में निर्णायक जीत दर्ज करके जनसंघ के संस्थापक और बंगाल मूल के दूरदर्शी हिंदूवादी राजनेता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अद्भुत श्रद्धांजलि दी है। सच कहूं तो आरएसएस के इस सुप्रसिद्ध सिपाही का कश्मीर में दिया हुआ सियासी बलिदान व्यर्थ नहीं गया। खासकर यह उपलब्धि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर भाजपा द्वारा उसे दिया हुआ बहुमूल्य वैचारिक तोहफा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत केवल सरकार बदलने की घटना नहीं होगी, बल्कि यह भारतीय राजनीति में 'पूर्वी भारत के वैचारिक परिवर्तन' का प्रतीक मानी जाएगी। इससे विपक्ष का शक्ति-संतुलन बदलेगा, भाजपा का राष्ट्रीय आत्मविश्वास बढ़ेगा और बंगाल की दशकों पुरानी राजनीतिक संस्कृति में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। कम शब्दों में कहा जाए तो भय हारा और भरोसा जीता है। भद्रलोक के हृदय परिवर्तन से सोनार बंगला के बहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिलने से हिंदुओं का मनोबल बढ़ेगा और बंगलादेशी घुसपैठियों से देश को मुक्ति मिलेगी।

इस शुभ घड़ी को दिखलाने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, भाजपा के राष्ट्रीय अध्ययन नितिन नवीन की सूझबूझ और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सियासी तेवरों का भी अहम योगदान है। वहीं, हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेताओं उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व सरमा के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं, पश्चिम बंगाल के राजनेता सुवेन्दु अधिकारी, दिलीप बोस जैसे कर्मठ नेताओं और भाजपा के 'बलिदानी' कार्यकर्ताओं के अथक संघर्ष का प्रतिफल है।

देखा जाए तो यह भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं और उनका हौसलाअफजाई करते रहने वाले स्थानीय और बाहरी नेताओं के संयुक्त प्रयासों का सकारात्मक नतीजा है, जिसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं। बंगलादेश की हिन्दू विरोधी मानसिकता और ग्रेटर बंगलादेश की थ्योरी ने पूर्वी भारत के हिंदुओं को इस कदर भयभीत कर दिया है कि अब उनके पास भाजपा के नेतृत्व में गोलबंद होने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लिहाजा, पहले कलिंग यानी उड़ीसा, फिर अंग यानी बिहार और अब बंग यानी पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत और भगवा की बुलंदी बहुत कुछ राजनीतिक चुगली करती है, जिसे समझने, और जनमानस को समझाने की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर में बसे पूर्वी भारत के कर्तव्यनिष्ठ आरएसएस/भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं की मानें तो यह उनके सामूहिक प्रयासों की विजय हैजो अनवरत रूप से जारी अथक जनसंघर्षों और कार्यकर्ताओं के बलिदानों की वजह से मिली है। लिहाजा इसके राजनीतिक निहितार्थ केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति, संघीय ढांचे और विपक्ष की रणनीति पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। वहीं, निकट भविष्य में पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया तक में इसकी अनुगूंज सुनाई पड़ेगी।

लिहाजा, इस अभूतपूर्व विजय के प्रमुख राजनीतिक निहितार्थ/मायने इस प्रकार होंगे: 1. पूर्वी भारत में भाजपा का निर्णायक विस्तार

पश्चिम बंगाल लंबे समय तक वामपंथ और बाद में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहां भाजपा की जीत यह संकेत देगी कि पार्टी अब हिंदी पट्टी से आगे निकलकर पूर्वी भारत में स्थायी राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। इससे ओडिशा, असम और पूर्वोत्तर में भाजपा की पकड़ और मजबूत होगी। अन्य राज्यों में विस्तार भी होगा।

2. ममता बनर्जी की राष्ट्रीय भूमिका कमजोर पड़ना: ममता बनर्जी विपक्षी राजनीति की सबसे आक्रामक नेताओं में मानी जाती रही हैं। बंगाल में हार होने पर उनकी 'राष्ट्रीय विकल्प' वाली छवि को गहरा झटका लगेगा। इंडिया गठबंधन की राजनीति में उनका प्रभाव कम हो सकता है और विपक्ष का नेतृत्व पुनः बिखर सकता है। जबकि राहुल गांधी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि उनकी टांग खींचने वाले सारे क्षेत्रीय नेता उनकी सटीक रणनीति से सियासी धूल फांकने को अभिशप्त हुए। इससे भविष्य में कांग्रेस लाभान्वित होगी।

3. कांग्रेस और वामपंथ का लगभग राजनीतिक अंत: पश्चिम बंगाल में पहले ही चुनाव भाजपा बनाम तृणमूल तक सिमटता दिख रहा है। भाजपा की जीत होने पर यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस और वामदलों की पारंपरिक राजनीति बंगाल में अप्रासंगिक हो चुकी है।

4. 'हिंदुत्व और कल्याणकारी राजनीति' मॉडल की सफलता: भाजपा ने बंगाल में राष्ट्रवाद, सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, नागरिकता और हिंदू पहचान के मुद्दों को कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़कर चुनावी रणनीति बनाई है। यदि यह सफल होती है, तो पार्टी इस मॉडल को अन्य राज्यों में भी और आक्रामक रूप से लागू करेगी।

5. बंगाल की राजनीतिक संस्कृति में बड़ा बदलाव: बंगाल लंबे समय तक वैचारिक राजनीति, वामपंथी विमर्श और क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति के लिए जाना जाता रहा है। भाजपा की जीत यह संकेत देगी कि बंगाल की राजनीति अब वैचारिक संघर्ष से निकलकर राष्ट्रीय ध्रुवीकरण और पहचान-आधारित राजनीति की ओर बढ़ रही है।

6. 2029 लोकसभा चुनाव की दिशा तय होगी: भाजपा द्वारा बंगाल जीत से 2029 लोकसभा चुनाव के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी। बंगाल की 42 लोकसभा सीटें राष्ट्रीय सत्ता संतुलन में बेहद महत्वपूर्ण हैं। भाजपा यह संदेश दे सकेगी कि उसका विस्तार अब दक्षिण और पूर्व भारत तक स्थायी रूप से हो चुका है।

7. संघ और भाजपा संगठन की रणनीति को वैधता: पश्चिम बंगाल में भाजपा का संगठन वर्षों तक कमजोर माना जाता था। यदि पार्टी सत्ता तक पहुंचती है, तो यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के दीर्घकालिक कैडर विस्तार मॉडल की बड़ी सफलता मानी जाएगी। सोशल और वैचारिक स्तर पर संघ की पैठ को भी मजबूती मिलेगी।

8. केंद्र-राज्य संबंधों में नया समीकरण: अब तक बंगाल और केंद्र सरकार के संबंध अक्सर टकरावपूर्ण रहे हैं। भाजपा सरकार बनने पर केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बढ़ेगा, जिससे निवेश, बुनियादी ढांचे और केंद्रीय परियोजनाओं को गति मिल सकती है। हालांकि विपक्ष इसे 'संघीय ढांचे के केंद्रीकरण' के रूप में भी प्रस्तुत कर सकता है।

9. पहचान और सुरक्षा राजनीति को बल: सीमा पार घुसपैठ, एनआरसी-सीएए, बांग्लादेश सीमा और जनसांख्यिकीय बदलाव जैसे मुद्दे बंगाल की राजनीति के केंद्र में आ जाएंगे। भाजपा की जीत इन मुद्दों को राष्ट्रीय बहस में और प्रमुख बना सकती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत केवल सरकार बदलने की घटना नहीं होगी, बल्कि यह भारतीय राजनीति में 'पूर्वी भारत के वैचारिक परिवर्तन' का प्रतीक मानी जाएगी। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक है।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

संक्षिप्त समाचार

डॉक्टर के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ठगी की कोशिश, टिकरापारा थाने में मामला दर्ज

रायपुर। राजधानी रायपुर में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है, जहां ठगों ने रामकृष्ण अस्पताल के एमडी डॉ. संदीप दवे के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से पैसे मांगने की कोशिश की। मामले की जानकारी मिलते ही डॉ. दवे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर टिकरापारा थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।डॉ. दवे के अनुसार, ठग उनके नाम और पहचान का दुरुपयोग करते हुए लोगों को मैसेज भेज रहे हैं। इसमें खुद को डॉक्टर बताते हुए किसी आपात स्थिति का हवाला देकर आर्थिक मदद मांगी जा रही है। इससे न केवल लोगों के ठगी का शिकार होने का खतरा बढ़ गया है, बल्कि उनकी व्यक्तिगत और संस्थान की साख पर भी असर पड़ सकता है।बताया जा रहा है कि यह पहली बार नहीं है जब उनके नाम का दुरुपयोग किया गया हो। इससे पहले भी इसी तरह की घटना सामने आ चुकी है, जिसके संबंध में उन्होंने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। उस शिकायत का विवरण भी पुलिस को सौंपा गया है।

फोन पर अश्लील बातें और व्हाट्सएप पर न्यूड फोनटो की मांग से

रायपुर। राजधानी रायपुर में एक नवविवाहिता ने फोन कॉल और व्हाट्सएप के जरिए लगातार परेशान किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल में कार्यरत बताई जा रही है। मामले में टिकरापारा थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है।शिकायत के अनुसार, 30 अप्रैल से एक अज्ञात नंबर से लगातार फोन कॉल आ रहे थे। कॉल करने वाला युवक आपत्तिजनक और अनुचित बातचीत करता था। विरोध करने पर वह अपशब्दों का प्रयोग करने लगा।पीड़िता ने बताया कि 4 मई को फिर से उसी नंबर से कॉल और संदेश आने लगे, जिनमें अशोभनीय सामग्री भी भेजी गई। लगातार हो रही इस हरकत से परेशान होकर महिला ने पुलिस से संपर्क किया और आरोपी के मोबाइल नंबर की जानकारी देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की।पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल के माध्यम से आरोपी की पहचान और लोकेशन ट्रेस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नशीली टेबलेट बेचते दो आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। रायपुर पुलिस ने नशीली टेबलेट की अवैध बिक्री पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। एण्टी क्राइम एवं साइबर यूनिट और टिकरापारा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि टिकरापारा क्षेत्र के गोकुल नगर स्थित शमशान घाट के पास कुछ संदिग्ध युवक प्रतिबंधित नशीली टेबलेट बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर टीम ने मौके पर दबिश दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बताए गए हुलिए के आधार पर दो संदिग्धों को चिन्हित किया। पुलिस को देखकर दोनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम कपिल तिवारी (19 वर्ष) निवासी दुर्ग और मोहम्मद अनीश (52 वर्ष) निवासी टिकरापारा रायपुर बताया। तलाशी के दौरान उनके पास से प्रतिबंधित नशीली टेबलेट स्पासमो और नाइट्रोसन-10 की कुल 73 गोलियां बरामद की गईं, जिनकी कीमत करीब 29,200 रुपये बताई जा रही है। आरोपियों से इन टेबलेट्स के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना टिकरापारा में नारकोटिक एक्ट की धारा 22(ख) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मोहम्मद अनीश पहले भी वर्ष 2025 में इसी तरह के मामले में पकड़ा जा चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और सप्लाई चेन की जानकारी जुटा रही है।

खारुन किनारे गांजा सौदा फेल, 3.6 किलो नशे संग 19 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। खारुन नदी के शांत किनारे अचानक पुलिस का शिकंजा कसता है और नशे का सौदा शुरू होने से पहले ही ध्वस्त हो जाता है—रायपुर के डीडी नगर इलाके में 3 किलो 600 ग्राम गांजा के साथ 19 वर्षीय युवक को रंगे हाथों दबोच लिया गया, जिसकी कीमत करीब 1.80 लाख रुपये आंकी गई है। यह पूरी कार्रवाई 04 मई 2026 को डीसीपी पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत थाना डीडी नगर पुलिस ने उस वक्त अंजाम दी, जब मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि एक युवक नदी किनारे संदिग्ध हालत में गांजा लेकर बिक्री के इरादे से खड़ा है, सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना देर किए मौके पर दबिश दी, चारों ओर से घेराबंदी की।

सुशासन तिहार-2026

मंत्री चौधरी ने ग्राम माकड़ीखूना में शिविर का किया निरीक्षण....

- वित्तमंत्री शिविर में पहुंचकर योजनाओं की जमीनी हकीकत की ली जानकारी, हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत बांटी गई सामग्री
- प्रदेश सहित जिले के विकास के लिए सरकार हरसंभव मदद कर रही: वित्त मंत्री

रायपुर/ संवाददाता

प्रदेश के वित्तमंत्री श्री ओ.पी. चौधरी आज उत्तर बस्तर कांकेर जिले के प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने सुशासन तिहार एवं बस्तर मुन्ने कार्यक्रम के अंतर्गत कांकेर विकासखण्ड के ग्राम माकड़ीखूना में आयोजित शिविर में पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। साथ ही विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत सामग्री का वितरण किया। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र के सहयोग से लंबे समय से चली आ रही माओवादी समस्या को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिससे जरूरतमंदों को आवास की सुविधा मिल रही है। वहीं महतारी वंदन योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में तेंदूपत्ता की खरीदी 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से की जा रही है, जिससे वन आश्रित परिवारों को लाभ मिल रहा है। सरकार प्रदेश सहित कांकेर जिले के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। साथ ही बस्तर क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विकास की व्यापक कार्ययोजना तैयार की जा रही है। कार्यक्रम में सांसद श्री भोजराज नाग ने कहा कि बस्तर क्षेत्र, जो लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहा, अब विकास की मुख्यधारा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कांकेर विधायक श्री आशाराम नेताम ने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से सरकार गांव-गांव पहुंचकर योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन कर रही है। कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने जानकारी दी कि सुशासन तिहार और बस्तर मुन्ने कार्यक्रम के तहत 14 अधोसंरचना एवं 31 व्यक्तिमूलक योजनाओं के संतृप्तिकरण के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभ मिल सके। शिविर में विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। खाद्य विभाग द्वारा 3 हितग्राहियों को राशन कार्ड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास की चाबी, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड तथा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। शिविर स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी भी दी गई।

चार दिन में 1 लाख 62 हजार लोगों की हुई जनगणना, 47 हजार घरों तक पहुंचे प्रगणक

रायपुर/ संवाददाता

रायपुर जिले में 1 मई से शुरू हुए घर-घर जनगणना के काम में चार दिन में प्रगणक 47 हजार 341 घरों तक पहुंच चुके हैं। 1 लाख 62 हजार 653 सदस्य इन घरों में निवासरत हैं। दरअसल नक्शा बनाने के बाद प्रगणक घर-घर जाकर लोगों से 33 सवालों के जवाब ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार रायपुर जिले में 3939 ब्लॉक बनाए गए है। वहीं 2438 ब्लॉक में प्रगणक तेजी से कार्य कर रहे हैं, बाकी 1501 ब्लॉक प्रोग्रेस में हैं। वहीं, प्रदेश की बात की जाए तो दो लाख से अधिक घरों तक प्रगणक अब तक पहुंच चुके हैं। ये सारे आंकड़े सोमवार के शाम 6.30 बजे तक सिस्टम में दर्ज हुए आंकड़े हैं। जो प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी जुटा रहा है, उसे पहले अपने-अपने एरिया का नक्शा बनाने कहा गया था। जिससे उन्हें अपने ब्लॉक के घरों की जानकारी हो, और बिना किसी परेशानी के वे अपने एरिया में काम पूरी सके। इससे इन्हें काफी राहत मिल रही है। एक प्रगणक के पास करीब 180-200 घर हैं। 16 से 30 अप्रैल तक स्वगणना फॉर्म भरने का ऑप्शन दिया गया था। जिसके माध्यम से प्रदेशभर में करीब 1 लाख 42 हजार लोगों ने स्वगणना फॉर्म भरा है। दरअसल स्वगणना फॉर्म भरने के बाद एक एसई आईडी मिलता है, जिसे संभालकर रखना होता है। जब प्रगणक घर पहुंचते है, तो इसी एसई आईडी के माध्यम से ही वे सत्यापन कर जनगणना फॉर्म भरते है। प्रगणक अब तक 273 आईडी का सत्यापन कर चुके हैं। जनगणना कार्य में लगे प्रगणकों और सुपरवाइजर की सुरक्षा के लिए जिला जनगणना अधिकारी ने पुलिस कमिश्नर रायपुर और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि कुछ स्थानों पर प्रगणकों के साथ मारपीट की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं। इनके साथ किसी प्रकार का विवाद व अप्रिय घटना न हो इसके लिए समस्त पुलिस थाना में पूर्व सावधानी बरतने और पुलिस सुरक्षा बल उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

फर्जी जॉब ऑर्डर का जाल,करोड़ों की ठगी, शिक्षक-क्लर्क गिरफ्तार

रायपुर। संवाददाता

व्हाट्सएप पर आया एक सरकारी नियुक्ति आदेश और उसी के साथ शुरू हुआ करोड़ों की ठगी का खेल, जहां हर लाइन में नौकरी का सपना था और हर साइन में भरोसे का जाल, रायपुर ग्रामीण में जब इस फर्जी आदेश की परत खुली तो पता चला कि यह सिर्फ एक मैसेज नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश थी, जिसमें मंत्रालय के नाम, सचिव और उप-सचिव के डिजिटल हस्ताक्षर तक का इस्तेमाल कर लोगों को फंसाया गया, कहानी की शुरुआत होती है 24 अप्रैल 2026 से, जब सामान्य प्रशासन विभाग के राजपाल बघेल ने थाना राखी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सोशल मीडिया पर एक फर्जी आदेश वायरल हो रहा है, जिसमें कई विभागों में भर्ती का दावा किया गया था और उसी के बहाने लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे थे, जैसे ही मामला सामने आया, पुलिस हरकत में आई और एक विशेष टीम बनाई गई, जिसने डिजिटल दुनिया के अंधेरे को खंगालना शुरू किया, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप ट्रेल और इलेक्ट्रॉनिक सबूत एक-एक कर खुलने लगे और फिर एक नाम सामने आया राजेश शर्मा उर्फ राजू, पुलिस की टीम सीधे राजनांदगांव के डोंगरगढ़ पहुंची, जहां दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, पूछताछ में जो सामने आया उसने पूरे खेल का नक्शा साफ कर दिया, राजेश शर्मा पिता डी.पी. शर्मा उम्र 53 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 01 खुटापारा डोंगरगढ़, जो पेशे से शिक्षक है, उसने अपनी आर्थिक तंगी और कर्ज के दबाव में यह जाल बुना और इस खेल में उसका साथी बना मनोज कुमार श्रीवास्तव पिता अमरेश श्रीवास्तव उम्र 52 वर्ष निवासी कुम्हारपारा डोंगरगढ़, जो एक प्राइवेट स्कूल में क्लर्क है, दोनों ने मिलकर कंप्यूटर पर फर्जी नियुक्ति आदेश तैयार किया।

मंत्री केदार कश्यप ने सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित इस जन चौपाल में मंत्री ने न केवल ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, बल्कि प्रशासन को सीधे जनता के द्वार पर खड़ा कर दिया।

नवा रायपुर में आईपीएल का रोमांच मैच 10 और 13 को

सचिव विकासशील ने सुरक्षा और सुविधाओं के लिए कड़े निर्देश......

रायपुर/ संवाददाता

नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आगामी 10 और 13 मई को होने वाले टाटा आईपीएल टी-20 मैचों के सफल आयोजन के लिए राज्य प्रशासन ने कमर कस ली है। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने आज मंत्रालय महानदी भवन में विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और आयोजन से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव के इन कड़े निर्देशों के बाद अब नवा रायपुर का प्रशासन क्रिकेट के इस महाकुंभ की मेजबानी के लिए पूरी तरह मुस्तैद है, जिससे दर्शकों को एक सुरक्षित और आनंदमयी अनुभव मिल सके। 10 मई 2026 को रॉयल चौलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस और 13 मई 2026 को रॉयल चौलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के मध्य मैच खेला जाएगा। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने स्पष्ट किया कि स्टेडियम में आने वाले हजारों दर्शकों की सुरक्षा और सुगम यातायात प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऑनलाइन बुकिंग के बाद रायपुर पहुंचने वाली दर्शकों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कमिश्नर रायपुर को विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पार्किंग एरिया और स्टेडियम के चारों ओर सीसीटीवी कैमरों का सघन जाल बिछाया जाएगा। बैरिकेडिंग और पार्किंग की जिम्मेदारी पुलिस, एनआरडीए और बीसीसीआई की संयुक्त टीम संभालेगी।

झारखंड शराब घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अनिल टुटेजा को अग्रिम जमानत, हाईकोर्ट ने दी सशर्त राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कथित झारखंड शराब घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत प्रदान की है। न्यायमूर्ति पी.पी. साहू की एकलपीठ ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि की दो जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने उन्हें जांच में पूर्ण सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित न करने के निर्देश भी दिए हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि टुटेजा जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो जांच एजेंसी को उनकी जमानत निरस्त कराने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी। हालांकि, इस मामले में राहत मिलने के बावजूद टुटेजा का जेल से बाहर आना फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के चर्चित डीएमएफ घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े प्रकरण में उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।

सचिन तेंदुलकर बनकर 45 लाख की धोखाधड़ी

रायपुर। संवाददाता

हुडको भिलाई निवासी सेवानिवृत्त बीएसपी कर्मचारी जयंत बागची ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश करने के नाम पर 45 लाख 18 हजार 998 रुपये की धोखाधड़ी का शिकार हो गया। प्रार्थी के मुताबिक आरोपितों द्वारा फेसबुक पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर एवं सुधा मूर्ति द्वारा भी निवेश के संबंध में कही जा रही बातों का वीडियो दिखाकर उसे झांसे में लिया गया। मामले में भिलाई नगर पुलिस ने धारा 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। प्रार्थी ने पुलिस को दर्ज रिपोर्ट में बताया है कि वह भिलाई इस्पात संयंत्र से सेवानिवृत्त कर्मचारी है इसके पूर्व में भारतीय सेना में भी अपनी सेवा दे चुका है। प्रार्थी 10 मार्च 2026 को अपने मोबाइल नंबर पर फेसबुक देख रहा था। प्रार्थी के मुताबिक उसमें भारत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कुछ बातें कही जा रही थीं एवं प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे सचिन तेंदुलकर एवं सुधा मूर्ति के द्वारा भी निवेश के संबंध में कही जा रही थीं। उपरोक्त बातों से प्रभावित होकर प्रार्थी ने उपरोक्त संबंध में लिंक हेतु रजिस्ट्रेशन किया। प्रारंभिक रूप से प्रार्थी की बात कृतिका से हुई जिसने उसे पंजीयन के लिए 18,999 रुपये देने कहा। प्रार्थी द्वारा नेट बैंकिंग के माध्यम से उक्त राशि प्रेषित करने के बाद उसका पंजीयन भी हो गया। दो दिन बाद कृतिका ने व्हाट्सएप कॉल कर एकाउंट मैनेजर सिद्धार्थ विपुल से बात कराई।

महाविद्यालय के बाउंड्रीवाल का होगा तत्काल सीमांकन

अनुशासन और कड़ी मेहनत ही सफलता का मूलमंत्र-टंकराम

- महाविद्यालय की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के दिए कड़े निर्देश

रायपुर/ संवाददाता

शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा में बुधवार को वार्षिक स्नेह सम्मेलन क्षितिज का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने जहाँ छात्र-छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रेरित किया, वहीं कॉलेज की सुरक्षा के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए परिसर की भूमि से तत्काल अतिक्रमण हटाने का सख्त आदेश दिया। राजस्व मंत्री के इस दौरे ने जहाँ कॉलेज के विकास और सुरक्षा को नई दिशा दी है, वहीं छात्रों के बीच जोश और प्रेरणा का संचार भी किया है। स्नेह सम्मेलन के दौरान कॉलेज प्रशासन और विद्यार्थियों ने परिसर की सुरक्षा एवं अतिक्रमण संबंधी समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। इस पर राजस्व मंत्री ने त्वरित संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया। कॉलेज की बाउंड्रीवाल के पास हुए बेजा कब्जे को तत्काल हटाया जाए। भविष्य में अतिक्रमण की गुंजाइश खत्म करने के लिए कॉलेज की पूरी भूमि का तत्काल सीमांकन किया जाए। छात्र-छात्राओं के लिए एक सुरक्षित और भयमुक्त शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना शासन की प्राथमिकता है। छात्रों को संबोधित करते हुए मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि वार्षिक स्नेह सम्मेलन केवल सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अवसर नहीं, बल्कि यह युवाओं के भीतर छिपी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता को निखारने का मंच है। उन्होंने युवाओं को सफलता

के तीन सूत्र दिए। उन्होंने कहा कि जीवन में संयम और नियम ही आपको भीड़ से अलग करता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल कड़ी मेहनत ही स्थायी परिणाम देती है। मत्री श्री वर्मा ने कहा कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें ताकि देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकें। कार्यक्रम के दौरान क्षितिज के मंच पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति की अनूठी छटा बिखरी। छात्र-छात्राओं ने लोक कला और संस्कृति पर आधारित रंगारंग प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। मंत्री श्री वर्मा ने शैक्षणिक सत्र और खेलकूद प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को पदक एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस गरिमामय अवसर पर पूर्व विधायक श्री शिवरतन शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अश्वनी शर्मा, महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापकगण सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए बुधवार को बलौदाबाजार जिले में जनसमस्या निवारण शिविरों का भव्य आयोजन किया गया। इन शिविरों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने अधिकारियों को कड़े तेवर दिखाते हुए स्पष्ट किया कि आम जनता और विशेषकर किसानों की समस्याओं के निराकरण में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी नगरपालिका भाटापारा, बलौदाबाजार और ग्राम मोहतरा के शिविरों को संबोधित करते हुए मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करना सुनिश्चित करें।

संक्षिप्त समाचार

आधुनिक खेती से किसान कुनाल कश्यप को मिली बेहतर आमदनी

बिलासपुर। जिले के तखतपुर विकासखंड के ग्राम बहतराई निवासी किसान श्री कुनाल कश्यप ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत संरक्षित खेती अपनाकर सफलता की नई मिसाल पेश की है। वर्ष 2024-25 में उद्यान विभाग की सहायता से उन्हें 4000 वर्ग मीटर में शेडनेट हाउस निर्माण हेतु अनुदान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने शेडनेट हाउस के अंदर हाईब्रिड पत्तागोभी के लगभग 20 हजार पौधों का रोपण किया, जिससे उन्हें पारंपरिक खेती की तुलना में अधिक लाभ मिलने लगा है। किसान श्री कुनाल कश्यप ने बताया कि पहले वे सामान्य तरीके से सब्जी की खेती करते थे, लेकिन उतना लाभ नहीं मिल पाता था। संरक्षित खेती तकनीक अपनाने के बाद उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ है। वर्तमान में 0.40 हेक्टेयर कृषि भूमि में की जा रही खेती से लगभग 70 से 90 क्विंटल उत्पादन का अनुमान है। इस खेती में लगभग 1 से 1.50 लाख रुपये की लागत आई है, जबकि बिक्री से 3 से 3.50 लाख रुपये तक की आय होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग के मार्गदर्शन और नई तकनीक के उपयोग से कम क्षेत्र और कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। किसान की इस सफलता से क्षेत्र के अन्य किसान भी संरक्षित खेती की ओर प्रेरित हो रहे हैं।

विजयपुर, टिकरापारा और बोदरी में 8 को सुशासन शिविर

बिलासपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में जिले में 1 मई से सुशासन तिहार का सफल आयोजन किया जा रहा है। गांव सहित नगरीय निकायों में भी जनसमस्या निवारण शिविरों के माध्यम से शासकीय योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने एवं लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में 8 मई को तखतपुर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत विजयपुर में सुशासन शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में क्षेत्र से लगे हुए ग्राम पोड़ीकला, परसाकापा, निगारबंद, पूरा, बहुरता, टिहुलाडीह, पड़रिया, चोरमा, पकरिया, बेलपान, टिकरी, दर्री, विजयपुर, लिम्हा, सिलतरा, ठाकुरकापा एवं करनकापा के ग्रामीण भी शामिल हो सकते है। साथ ही नगर निगम बिलासपुर क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्र 38, 39 एवं 41 के वार्डवासियों के लिए गुजराती समाज भवन टिकरापारा एवं नगर पालिका परिषद बोदरी में वार्ड क्र. 1,2,3 हेतु वार्ड क्रमांक 2 शासकीय प्राथमिक शाला बोदरी में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, ड्राईविंग लाईसेंस, स्वास्थ्य सेवाएं तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं सहित अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कलेक्टर ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे अपने निकटतम शिविर में पहुंचकर अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ उठाएं और शासन की योजनाओं से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान कराएं। सुशासन तिहार-2026 का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना तथा विकास कार्यों में गति लाने के साथ ही आम जनता, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से सीधा संवाद स्थापित करना है।

जूनियर रेडक्रॉस के 30 बच्चों एवं शिक्षकों का दल रायपुर रवाना

बिलासपुर। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर बिलासपुर जूनियर रेडक्रॉस के 30 बच्चों एवं शिक्षकों के दल को शहर के नया बस स्टैंड से रायपुर के लिए रवाना किया गया। दल को डॉ. बी.एल. गोयल, चेयरमैन प्रबंध समिति रेडक्रॉस द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान कराया गया। रायपुर रवाना हुआ यह दल विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों में भाग लेकर बिलासपुर जिले का प्रतिनिधित्व करेगा। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने सभी बच्चों एवं शिक्षकों को शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर सर्वश्री सौरभ सक्सेना, आदित्य पांडेय, लक्ष्मीनारायण मिश्रा, मनीष मिश्रा, धरम लाल साहू, रवि राज साहू, गीतेश्वरी चन्द्रा एवं सौखी लाल यादव उपस्थित रहे।

कलेक्टर-एसएसपी ने भी लिया शिविर का जायजा

उच्चभट्ठी शिविर में शामिल हुए जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी

बिलासपुर। जिले के गांव-गांव और शहर में सुशासन तिहार का सिलसिला जारी है। शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की जानकारी के साथ ही योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसी क्रम में आज बिल्हा ब्लॉक के उच्चभट्ठी में आयोजित सुशासन शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी शामिल हुए। उन्होंने लोगों से शिविर का अधिक से अधिक लाभ लेने की भी अपील की। इस अवसर पर कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, एसडीएम मनीष साहू, सीईओ जनपद कुमार लहरे सहित जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष सूर्यवंशी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन तिहार के जरिए लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही सुशासन तिहार का उद्देश्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं का तत्परता से निराकरण करें। शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन

सुनिश्चित करने और लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण करने के उद्देश्य से सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। सुशासन तिहार के तहत सरकार लोगों के गांव, घर तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रही है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति आप लोगों की जागरूकता का परिचायक है।

शिविर में आज कुल 196 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 161 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शेष 35 आवेदनों के निराकरण के लिए संबंधित विभागों को समयसीमा निर्धारित की गई है। शिविर में खाद्य विभाग द्वारा 9 हितग्राहियों को राशन कार्ड का वितरण, 4 हितग्राहियों को उज्जवला गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। उच्चभट्ठी के प्रफुल्ल कुमार, कमल बाई मंडला, नरोत्तम कुमार सूर्यवंशी और पिंकी कोशले को जॉब कार्ड का वितरण किया गया। आवास पूर्ण करने पर 9 हितग्राहियों आवास पूर्णता प्रमाण पत्र एवं श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना अंतर्गत ग्राम उच्चभट्ठी की कुमारी पूजा और नंदनी को 20-20 हजार चेक दिया गया। उच्चभट्ठी के ही श्रीमती राम प्यारी सूर्यवंशी एवं किशन कन्हैया सूर्यवंशी को श्रमिक पंजीयन कार्ड का वितरण किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयुष खरे, तनिषा, सृद्धि एवं अयांश का अन्नप्राशन कार्यक्रम किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने शिविर में बड़ी संख्या में बीपी, शुगर की जांच कराई। स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद विभाग द्वारा दवाईयों का वितरण किया गया।

जब सराफा अध्यक्ष कमल सोनी बने 'झालमुड़ी वाले': बंगाल में भाजपा की जीत पर शहर में दिखा जश्न का अलग रंग

- सराफा एसोसिएशन का अनूठा सेलिब्रेशन: बंगाल की जीत पर शहर में बांटी गई झालमुड़ी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए शहर में अनोखे अंदाज़ में जश्न मनाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के बीच झालमुड़ी बांटकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। इस मौके पर कमल सोनी ने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन व सौरभ सिंह की नेतृत्व में पिछले डेढ़ महीने से बिलासपुर सराफा के कुछ कार्यकर्ता लगातार पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत के लिए मेहनत कर थे, आज इस जीत के बाद बंगाल की जनता को साधुवाद देते हुए कहा कि ऐसे अवसर पर खुशी मनाना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत जनता के विश्वास और विकास की जीत है। उन्होंने इसे देशभर में पार्टी के बढ़ते प्रभाव का संकेत बताया। जश्न के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने एक-दूसरे को बधाई दी। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भी उत्साह के साथ इस जीत का स्वागत किया और झालमुड़ी का आनंद लेते हुए खुशी साझा की। शहर में इस आयोजन ने एक अलग ही माहौल बना दिया।

ग्रीष्मकालीन भीड़ के दौरान यात्रियों को राहत किफायती दरों पर खानपान सेवा की उपलब्ध

बिलासपुर। ग्रीष्मकालीन मौसम के दौरान ट्रेनों में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए सामान्य श्रेणी (जनरल कोच) में यात्रा करने वाले यात्रियों की विशेष सुविधा तथा उन्हें किफायती दरों पर स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंडल के बिलासपुर, उसलापुर, रायगढ़, अनूपपुर रेलवे स्टेशनों पर इकोनॉमी मील (जनता खाना) के स्टॉल खोले गए हैं । यह स्टॉल प्लेटफॉर्म के साथ ही साथ विशेष रूप से ट्रेनों के जनरल कोच के सामने लगाए जा रहे हैं, ताकि सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को आसानी से किफायती एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध हो सके। यह पहल मंडल रेल प्रबंधक श्री राकेश रंजन के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनुराग कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में शुरू की गई है। इस सुविधा का विस्तार मंडल के अन्य प्रमुख स्टेशनों में भी शीघ्र प्रारंभ करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि अधिकाधिक यात्रियों को इस जनहितकारी सुविधा का लाभ मिल सके। इन स्टॉलों में यात्रियों को मात्र ?20/- में पूड़ी-सब्जी अथवा लेमन राइस जैसे पौष्टिक भोजन विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों की पेयजल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ?14/- में 1 लीटर पैकेज्ड पेयजल रेल नीर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे यात्रियों को यात्रा के दौरान आवश्यक खाद्य एवं पेय सामग्री उचित मूल्य पर आसानी से उपलब्ध हो रही है साथ ही उन्हें भोजन प्राप्त करने के लिए अनावश्यक भाग-दौड़ नही करनी पड़ रही है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि ग्रीष्मकालीन मौसम में अत्यधिक भीड़ के दौरान 'इकोनॉमी मील (जनता खाना)' जैसी पहल सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

जनादेश भाजपा के साथ:पश्चिम बंगाल ने चुना नया रास्ता

- भाजपा की प्रचंड जीत से नया बंगाल और सशक्त बंगाल का होगा उदय : कौशिक
- पश्चिम बंगाल, असम, की जीत पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौशिक ने कार्यकर्ताओं को दी शुभकामनाएं

बिलासपुर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा के जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ-साथ कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं एवं बधाई दी है साथ ही पश्चिम बंगाल की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जीत से एक नया बंगाल और सशक्त बंगाल का उदय हुआ है, पश्चिम बंगाल कि जनता अब तुष्टिकरण और अराजकता की राजनीति से त्रस्त हो चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी लोककल्याण नीतियों के प्रती वहां की जनता का अटूट विश्वास इस चुनाव में एक क्रांतिकारी परिणाम लेकर आया है। उन्होंने कहा की बंगाल की जीत केवल एक आकड़ो या पार्टी की जीत नहीं यह जीत दशकों से दबे उन लोगों की है जिनके हक को छिना जा रहा था, यह जीत पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के कई दशकों तक की गई मेहनत और धैर्य का प्रमाण है। बंगाल की माँ-माटी-मानुष को शत शत प्रणाम इस महाविजय से मानो बंगाल की शस्य श्यामला भूमि पर वंदे मातरम का सामूहिक जयघोष हुआ है। यह विजय हमारे प्रेरणास्त्रोत डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की धरती पर राष्ट्रवाद और सोनार बंगला के स्वप्न का उदय है। उन्होने कहा कि बंगाल की जनता बताया है कि अराजकता और भ्रष्टाचार चरम पर हो तो अर्श से फर्श तक लाने में समय नही लगता बंगाल में टीएमसी की हार इसका स्पष्ट उदाहरण है जिसे जनता ने उखाड़ फेका है और विकास का मार्ग अपनाया है और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। इसके लिए पश्चिम बंगाल की जनता का आभार है और निश्चित ही इस विश्वास को अटूट विश्वास बनाए रखने में भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि रुझान यह भी दर्शाते हैं कि युवा मतदाता विकास, विश्वसनीयता और जनता के साथ मजबूत जुड़ाव को महत्व देते हैं। इसके साथ ही भाजपा ने असम राज्य में हैट्रिक करते हुए प्रचंड जीत हसील की है इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा और जनता के बीच का सबंध अटूट विश्वास का सबंध है।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी बिलासपुर को बड़ी सौगात: 5.55 करोड़ से बनेगा आधुनिक आरसीसी बॉक्स नाला

जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

बिलासपुर। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव की पहल पर शहर के प्रमुख क्षेत्र में जल भराव की समस्या से निजात मिलने वाली है। उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा बिलासपुर को एक बड़ी सौगात देते हुए अधोसंरचना मद अंतर्गत ?5 करोड़ 55 लाख 87 हजार की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से कुंदन पैलेस से सहारे गली होते हुए बस स्टैंड तक 3म3 मीटर के आधुनिक आरसीसी बॉक्स नाले का निर्माण किया जाएगा। इस नाले की मांग बहुत पुरानी थी,जिसके बन जाने से शहर के एक प्रमुख क्षेत्र में बारिश के दिनों में होने वाली जल भराव की समस्या से मुक्ति मिलेगी। नाला निर्माण के बाद शहर के श्रीकांत वर्मा मार्ग, तालापारा मगरपारा और हंसा विहार जहां हर साल जल भराव होता हैं,उससे राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के भारसाधक मंत्री श्री अरुण साव के सतत प्रयासों और प्रभावी मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप बिलासपुर शहर को जल निकासी व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु एक महत्वपूर्ण सौगात मिली है। लंबे समय से लंबित जलभराव की समस्या के समाधान की दिशा में राज्य शासन द्वारा नगर पालिक निगम बिलासपुर को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अधोसंरचना मद अंतर्गत ?5 करोड़ 55 लाख 87 हजार की राशि स्वीकृत की गई है।यह स्वीकृति उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव की प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रदान की गई है, जिनके द्वारा शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर जीवन-स्तर उपलब्ध कराने पर लगातार जोर दिया जाता रहा है। उनके निर्देशन में नगरीय निकायों की आवश्यकताओं के आधार पर योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए उन्हें शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जा रही है। उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव के मार्गदर्शन में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि परियोजना का क्रियान्वयन पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किया जाए। शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए तथा छत्तीसगढ़ वर्क्स डिपार्टमेंट मैनुअल एवं विभागीय प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। परियोजना के प्रत्येक चरण में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु जियोटैग्ड फोटोग्राफी को अनिवार्य किया गया है, जिससे कार्यों की वास्तविक प्रगति का सटीक आकलन किया जा सके। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने कहा कि यह परियोजना बिलासपुर में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

कथित वायरल वीडियो पर भाजपा नेता ने कहा छवि धूमिल करने का प्रयास किया...

- आपसी लेनदेन को भ्रष्टाचार बताना गलत '
- कथित पत्रकार सूर्य प्रकाश सूर्यकांत की पचपेड़ी थाना में की गई शिकायत

बिलासपुर। बिलासपुर में सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित वीडियो को लेकर भाजपा नेताओं ने प्रेसवार्ता कर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि चंद्रप्रकाश सूर्या और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि खिलावन पटेल ने आरोप लगाया कि उनके बीच हुए सामान्य आर्थिक लेनदेन को तोड़-मरोड़ कर भ्रष्टाचार का रूप देने की कोशिश की गई है, जिससे उनकी राजनीतिक छवि धूमिल हो रही है। क्या है पूरा मामला- नेताओं के अनुसार, 29 अप्रैल 2026 को मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुकुर्दीकला में प्रस्तावित रेत घाट को लेकर जनसुनवाई आयोजित थी। इसी दौरान चंद्रप्रकाश सूर्या को किसी कार्य के लिए तत्काल पैसों की आवश्यकता पड़ी, जिस पर उन्होंने अपने पुराने मित्र खिलावन पटेल से सहायता मांगी। खिलावन पटेल ने मौके पर ही अपनी जेब में मौजूद राशि—लगभग 25 हजार रुपये—बिना किसी शर्त के उन्हें दे दी। बाद में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सूर्या के कहने पर राशि गिन ली गई, ताकि लौटाते समय कोई विवाद न हो। यह पूरा लेनदेन सार्वजनिक स्थान पर, लोगों की मौजूदगी में हुआ। वीडियो बनाकर छवि को धूमिल किया गया दुरुपयोग- प्रेसवार्ता में बताया गया कि उसी

दौरान वहां मौजूद पचपेड़ी निवासी कथित पत्रकार सूर्य प्रकाश सूर्यकांत ने इस लेनदेन का वीडियो बना लिया। आरोप है कि बाद में उन्होंने इस वीडियो के आधार पर अपने पोर्टल झ्द्धद्द स्न्हृद्दद्द ड्डश्वद्बष्द्ध पर भ्रामक खबर प्रकाशित कर इसे रेत घाट प्रबंधन और भ्रष्टाचार से जोड़ दिया। नेताओं का दावा है कि उक्त पत्रकार ने पहले वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी थी और बाद में बिना किसी ठोस प्रमाण के खबर प्रकाशित कर दी। रेत घाट से कोई संबंध नहीं: चंद्रप्रकाश सूर्या- चंद्रप्रकाश सूर्या और खिलावन पटेल ने स्पष्ट किया कि उनका कुकुर्दीकला रेत घाट या उससे जुड़े किसी भी प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है। जनसुनवाई में उनकी उपस्थिति केवल जनप्रतिनिधि के रूप में थी। उन्होंने कहा कि यदि कोई अवैध लेनदेन करना होता, तो वह सार्वजनिक स्थल पर नहीं किया जाता। एफआईआर और कानूनी कार्रवाई- इस मामले में दोनों नेताओं ने संबंधित पत्रकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले उन्हें लीगल नोटिस भेजा गया और बाद में थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। आरोप है कि बिना पुष्ट जानकारी के भ्रामक खबर प्रकाशित कर भयादोहन (ब्लैकमेलिंग) का प्रयास किया गया। नेताओं ने कहा कि वे इस प्रकरण में मानहानि का दावा भी दायर करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। राजनीतिक छवि धूमिल करने की साजिश का आरोप- प्रेसवार्ता में नेताओं ने कहा कि वे लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरह की साजिश रची गई है। उन्होंने इसे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताते हुए कहा कि उनकी बढ़ती सक्रियता और लोकप्रियता से कुछ लोग असहज हैं।

एथेनाल विस्थापन आंदोलन की उम्र दराज महिलाएं आज भी प्रताड़ना झेलने मजबूर

बेमेतरा। एथेनाल विस्थापन आंदोलन की उम्र दराज महिलाएं प्रताड़ना झेलने मजबूर हैं यह जानकारी देते हुए संतोष साहू, खेमराम साहू, दौना यादव, अजिताभ मिश्रा,नरेश साहू, सिद्दीक खान,चंदन साहू,गायत्री जोगी ने बताया कि इस ज़माने में गलत को गलत कहना ही गलत है.इन लोगों ने बताया कि पथर्रा रांका में एथेनाल प्लांट के विरोध की अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करने करवाकर बायोटेक एथेनाल प्लांट मालिक आज भी निर्बाध गति से धुंआ, बदबू और गंदा पानी उगल रहा है।इसका विरोध को पुलिस प्रशासन के दम पर दमन करके बायो टेक फ्यूल्स को खुली छूट दी जा चुकी है।गांव को प्रदूषण से बचाने, भारत के संविधान की धारा 21, जीने के अधिकार के तहत शांति पूर्ण विरोध करने वालों को सबक सिखाने, थोक के भाव से एफआईआर दर्ज की गई थी। अब प्लांट के आतंक को अपनी नियति मान कर चुप बैठ गए ग्रामीणों पर पुराने केस खोल कर एक बार पुनः कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में पुलिस टीम आज पथर्रा के ग्राम पंचायत में कैंप करके एफआई आर के नामजद लोगों के विवेचना कार्यवाही कर रही है।प्रशासनिक कार्यवाही की हद तो ये है कि 90 वर्ष की महिला गंगा साहु और परीक्षा दिलाने वाले छात्र हेमंत साहू दिनेश साहू तक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि ग्रामीणों की आवाज और मांग पर एक भी कार्यवाही नहीं की गई है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि महिला आयोग के उस आदेश को रद्दी की टोकरी में फेक दिया गया है,जिसमें रोहित सचदेव पर एफ आई आर की अनुशंसा की गई थी।आज पानी के लिए पूरे क्षेत्र की स्थिति गंभीर और दयनीय है, ऐसे क्रिटिकल वाटर जोन में एथेनाल जैसे भारी पानी बर्बाद करने वाले प्लांट को तरजीह दी जा रही है, जबकि पूरे जिले में कृषि कर अपने जीवन यापन करने वालों पर धान के नाम पर प्रतिबंध की कार्यवाही की जा रही है आगे बताया गया है। विगत दिनों में प्रताड़ित ग्रामीणों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर राखी है,। उच्च न्यायालय के डर से एस डी एम ने विगत दिन आनन फानन में बेक डेट में 151 का मुकदमा खारिज किया गया है।जिसमें एक साल से ऊपर चले मुकदमे में छह माह चलने की बात लिखी गई है। जिस पर उच्च न्यायालय में संज्ञान लिया है।वर्तमान में पीड़ित ग्रामीणों को न्याय की उम्मीद उच्च न्यायालय से है। जिसके लिए परिवाद दायर किया गया है।

एक दूसरे को खिलाई झालमुरी-मिठाई, भाजपाइयों ने मनाया तीन राज्यों में मिली जीत का जश्न

सरायपाली। पश्चिम बंगाल, असम एवं पांडिचेरी में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में सरायपाली में हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ भव्य विजय उत्सव मनाया गया। मेन रोड स्थित जन आशीर्वाद कार्यालय (सांसद रूपकुमारी चौधरी के कार्यालय के समक्ष) में भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने आतिशबाज़ी कर, फटाके फोड़कर एवं मिठाइयाँ वितरित कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। पूरे क्षेत्र में उत्सव का उल्लासपूर्ण वातावरण रहा। यह विजय मात्र चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि जन-जन के अटूट विश्वास, समर्पण और राष्ट्रहित के प्रति दृढ़ संकल्प की सशक्त अभिव्यक्ति है। यह सफलता विकास, सेवा और सुशासन के एक नए स्वर्णिम अध्याय के शुभारंभ का संकेत देती है। भाजपा जिला अजा मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अनेक वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी ने एक स्वर में पार्टी की नीतियों, विकास कार्यो एवं जनकल्याणकारी योजनाओं पर अटूट विश्वास व्यक्त करते हुए संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लिया। यह विजय उत्सव न केवल खुशी का प्रतीक रहा, बल्कि कार्यकर्ताओं के उत्साह, एकजुटता और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का भी परिचायक बना। इस कार्यक्रम में अनेक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से पूर्व कार्यकारी भाजपा जिलाध्यक्ष संजय शर्मा, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष विपिन उपवेजा, पिछड़ा वर्ग कल्याण सलाहकार परिषद छ. ग. प्रदेश सदस्य कामता पटेल, नगरीय निकाय प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक चन्द्रकुमार पटेल, किसान मोर्चा संभाग प्रभारी धनेश नायक, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष पुष्पलता चौहान,अजा मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रमोद सागर जनपद उपाध्यक्ष मुकेश चौधरी, प्राधिकृत अध्यक्ष एवं जनभागीदारी समिति अध्यक्ष महेन्द्र सिंह, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिला संयोजक तोषनाथ यादव, महिला मोर्चा जिला महामंत्री तारेश्वरी नायक, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला महामंत्री लालकुमार पटेल, जनपद पंचायत सभापति उद्धव नंद, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनोज दास, महिला मोर्चा जिला मंत्री वर्षा साहू, मंडल महामंत्री विदित धनानिया, मंडल महामंत्री सुरोतीलाल लकड़ा, मंडल उपाध्यक्ष तरुण बारीक, मंडल कोषाध्यक्ष जागेश्वर चन्द्रा, पूर्व पार्षद जयप्रकाश यादव, पार्षद प्रतिनिधि आशीष सेन, पार्षद प्रतिनिधि देवराज चौहान, जनपद सदस्य प्रतिनिधि शिव पटेल, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष रोहित साहू, अजा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मोहन चौहान, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सोहन पटेल, उमाकांत मिश्रा, नरेन्द्र प्रधान, नकुल चौहान, गोविन्द प्रधान एवं प्रकाश सिंह पारेश्वर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

घोटमर्रा उपकेंद्र में 5 एमवीए ट्रांसफार्मर स्थापित, 11 गांवों को मिली बेहतर बिजली सुविधा

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (दुर्ग क्षेत्र) द्वारा ग्रामीण विद्युत अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। साजा संभाग के देवरबीजा वितरण केंद्र अंतर्गत 33/11 केवी घोटमर्रा उपकेंद्र की क्षमता बढ़ाने का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग को ध्यान में रखते हुए, उपकेंद्र में लगे पुराने 3.15 एमवीए ट्रांसफार्मर को हटाकर उसकी जगह 5 एमवीए क्षमता का नया पावर ट्रांसफार्मर स्थापित कर उसे सफलतापूर्वक ऊर्जीकृत (चार्ज) किया गया है। यह कार्य कार्यपालक निदेशक संजय खंडेलवाल के मार्गदर्शन एवं अधीक्षण अभियंता आर.के. मिश्रा के नेतृत्व में संपन्न हुआ।

11 गांवों के 2400 से अधिक उपभोक्ताओं को सीधा लाभ

इस क्षमता वृद्धि से घोटमर्रा, हड़गांव, भेड़नी, चोटमर्रा, केछवई, कड़ई, हाड़ाहुली, कातुलबोड, मोतेसरा, रौद्र और डरजरा सहित कुल 11 गांवों के लगभग 2410 घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से बेहतर बिजली आपूर्ति की मांग कर रहे ग्रामीणों को अब राहत मिलेगी।

वोल्टेज समस्या से राहत, किसानों को मिलेगा फायदा

नए ट्रांसफार्मर के लगने से क्षेत्र में वोल्टेज की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। इससे किसानों को सिंचाई कार्यों के लिए पर्याप्त और स्थिर बिजली उपलब्ध होगी, वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को भी गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलेगी।

तकनीकी टीम के समन्वय से कार्य हुआ सफल

इस कार्य को सफल बनाने में विभागीय अधिकारियों एवं तकनीकी स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस दौरान कार्यपालन अभियंता एस.के. राय एवं एम.के. शुक्ला, सहायक अभियंता सी.एल. वर्मा, जी.पी. बंजारे तथा कनिष्ठ अभियंता अभिषेक राठी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

गर्मी में भी नहीं होगी बिजली ट्रिपिंग की समस्या

अधिकारियों के अनुसार, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ने से अब क्षेत्र में बढ़ते विद्युत लोड को आसानी से प्रबंधित किया जा सकेगा। इससे गर्मी के मौसम में भी बिजली ट्रिपिंग जैसी समस्याओं में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियां विकास में बाधक : डॉ. दिनेश मिश्र

जादू, टोने का अस्तित्व नहीं, अंधविश्वास में न फंसे

रायपुर। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ. दिनेश मिश्र ने कहा अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियां स्वस्थ समाज के विकास में बाधक हैं, सामाजिक कुरीतियां एवं अंधविश्वास मिटाने के लिए जागरूकता ज़रूरी है। जिसके लिए हर व्यक्ति को आगे आना होगा। समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता आवश्यक है यह केवल बौद्धिक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के भविष्य, उसके स्वास्थ्य, उसकी आर्थिक स्थिरता और उसकी मानवीय गरिमा से गहराई से जुड़ा हुआ है। डॉ. मिश्र ने विमतारा सभागृह में सामाजिक कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा पिछले 30 वर्षों में छत्तीसगढ़ के विभिन्न ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अंधविश्वास, विशेष रूप से टोनही प्रथा (डायन प्रथा) के खिलाफ काम करते हुए मैंने एक गहरी सच्चाई को बार-बार महसूस किया है अज्ञानता,गरीबी और जागरूकता की कमी से अंधविश्वास बनता और बढ़ता हैं और अफवाहें इनको मजबूत करते हैं। जहां संसाधनों की कमी होती है, वहां असुरक्षा बढ़ती है, और जहां असुरक्षा होती है, वहां भय पैदा होता है। यही भय अंधविश्वास का आधार बनता है।यह जानना जरूरी है कि गांवों में वैज्ञानिक सोच क्यों जरूरी है, आज भी जब किसी गांव में कोई बच्चा बीमार पड़ता है, तो कई परिवार सबसे पहले अस्पताल की ओर नहीं जाते, बल्कि बैगा-गुनिया या ओझा के पास जाते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास प्रणाली का हिस्सा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन इसका परिणाम अक्सर दुखद होता है, इलाज में देरी, बीमारी का बढ़ना, और कई बार जान तक चली जाना। इसी तरह, जब कृषि या और कोई परिवारिक, निजी समस्या आती है, तो वैज्ञानिक कारणों–जैसे मिट्टी की उर्वरता, जलवायु परिवर्तन या बीज की गुणवत्ता, स्वयं की लापरवाही की बजाय किसी व्यक्ति पर जादू टोना करने का आरोप लगाया जाता है। यह आरोप अक्सर महिलाओं पर लगता है, जिन्हें डायन घोषित कर दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप हिंसा, सामाजिक बहिष्कार और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन होता है। हमारा संविधान, विशेष रूप से अनुच्छेद 51ए(एच), हर नागरिक को यह कर्तव्य देता है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। लेकिन केवल कानून बना देने से सोच नहीं बदलती। सोच बदलने के लिए संवाद, विश्वास और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसलिए ग्रामीण अंचल में वैज्ञानिक सोच की आवश्यकता होती है। डॉ दिनेश मिश्र ने कहा- पिछले वर्षों में काम करते हुए हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं, जो इस दिशा में काम करने वाले हर व्यक्ति और संगठन के लिए उपयोगी हो सकती हैं। पहली बात कई बार भय तथ्यों से ज्यादा शक्तिशाली साबित होता है। जब कोई व्यक्ति डरा होता है, तो वह तर्क नहीं सुनता, वह समाधान खोजता है। इसलिए अगर हम सीधे यह कह दें कि आप जो मानते हैं वह गलत है, तो हम संवाद का रास्ता बंद कर देते हैं। इसके बजाय हमें पहले सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर धीरे-धीरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर ले जाना चाहिए। दूसरी बात, बताने से ज्यादा प्रभावी है करके दिखाना। जब हम चमत्कारों के पीछे के विज्ञान को सरल प्रयोगों के माध्यम से दिखाते हैं, तो लोग खुद निष्कर्ष निकालते हैं। जब एक ग्रामीण यह देखता है कि जो उसे चमत्कार लगता था, वह दरअसल एक साधारण वैज्ञानिक प्रक्रिया है, तो उसकी सोच में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन थोपे गए ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव से आता है। तीसरी बात विज्ञान को जीवन और आजीविका से जोड़ना जरूरी है। अगर वैज्ञानिक सोच केवल किताबों तक सीमित रहे, तो उसका प्रभाव आसीमित रहेगा। लेकिन जब हम इसे खेती, स्वास्थ्य, वन प्रबंधन और आजीविका से जोड़ते हैं, तो इसका सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर एक परिवार ओझा के इलाज पर हजारों रुपये खर्च करता है, तो वही पैसा अगर स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका में निवेश हो, तो उनका जीवन बेहतर हो सकता है। सामाजिक संगठन पहले से ही समुदायों के साथ गहराई से जुड़े हुए होते हैं। जो वनाधिकार, महिला सशक्तिकरण, आजीविका और स्थानीय शासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना कोई अलग या अतिरिक्त कार्य नहीं है, बल्कि यह आपके हर प्रयास की नींव को मजबूत करने का माध्यम है। वे इस दिशा में तीन महत्वपूर्ण और व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं।हर प्रशिक्षण और बैठक में तर्कशीलता को शामिल करें। चाहे वह वनाधिकार कानून पर प्रशिक्षण हो, स्वयं सहायता समूह की बैठक हो या वनोपज प्रबंधन का सत्र–हर जगह ÷ऐसा क्यों होता है÷ जैसे सवालों को शामिल करें। केवल 10-15 मिनट का एक छोटा सत्र भी लोगों की सोच को प्रभावित कर सकता है। दूसरा स्थानीय स्तर पर विज्ञान संचारकों का निर्माण करें। गांव के युवा, आशा कार्यकर्ता, दाई या शिक्षक–ये सभी वैज्ञानिक सोच के वाहक बन सकते हैं। उन्हें सरल प्रयोगों और उदाहरणों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा सकता है, ताकि वे अपने समुदाय में वैज्ञानिक जानकारी को सहज और प्रभावी तरीके से साझा कर सकें। तीसरा अंधविश्वास से जुड़ी घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया दें। जब किसी महिला को डायन घोषित किया जाता है या किसी व्यक्ति पर टोना-टोटका का आरोप लगाया जाता है और उसे प्रताड़ित किया जाता है, तो यह केवल एक सामान्य सामाजिक घटना नहीं होती, बल्कि यह पूरे, कानून व्यवस्था, शांति,विकास कार्य को प्रभावित करती है। ऐसे मामलों में कानूनी और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से तुरंत हस्तक्षेप करना आवश्यक है। इससे न केवल पीड़ित को न्याय मिलता है, बल्कि संगठन की विश्वसनीयता भी बढ़ती है। डॉ दिनेश मिश्र ने कहा- आने वाले वर्षों में हमारे सामने नई चुनौतियाँ होंगी। जलवायु परिवर्तन, नई बीमारियाँ, और डिजिटल माध्यमों से फैलने वाली अफवाहें–ये सभी सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित करेंगी। अगर हम अभी से वैज्ञानिक सोच को मजबूत नहीं करते, तो हर नई समस्या के साथ नए अंधविश्वास जन्म लेंगे। डॉ मिश्र ने कहा जब आम लोग डर और भ्रम से मुक्त होकर तर्क और प्रमाण के आधार पर निर्णय लेने लगें। जब वे तथाकथित अदृश्य शक्तियों से डरने के बजाय दिखाई देने वाले तथ्यों पर सवाल उठाने लगें, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव है।

भारतीय जनता पार्टी के तीन राज्यों पर ऐतिहासिक जीत पर हार्दिक बधाई

भारतीय जनता पार्टी की यह जीत विकास और सुशासन की जीत : अशोक जैन

बलौदाबाजार। विधानसभा चुनाव 2026 में पश्चिम बंगाल सहित असम एवं पुडुचेरी में निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के साथ ही हिंदुत्व का परचम लहराते हुए भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास के साथ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अराजकता और भय युक्त राजनीति से परे होकर सुशासन और सर्वांगीण विकास पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए अप्रत्याशित परिणाम दिया गया। नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन ने बताया कि सबका साथ सबका विश्वास व सबका विश्वास के मूल मंत्र को आत्मसात कर जनता ने भाजपा के प्रति अपना भरोसा जताया जिसके फलस्वरुप तीन राज्यों के निकले परिणाम में भाजपा को विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली है इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, केबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, सहित क्षेत्रीय सांसद बृजमोहन अग्रवाल, लक्ष्मी वर्मा सहित छत्तीसगढ़ राज्य के शीर्ष नेताओं के कुशल मार्गदर्शन एवं दी गई जिम्मेदारी पर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर भाजपा पार्टी व प्रत्याशी के पक्ष में सजगता व मेहनत के साथ कार्य किया, इसके लिए यह जीत मिली है, सभी को बधाई देते हुए जीत पर हर्ष व्यक्त कर नगर बलौदा बाजार में पटाखे फोड़ते हुए मिठाइयां बांटी गई, नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन सहित पार्षद गणों ने भारतीय जनता पार्टी के तीन राज्यों पर जीत पर बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं दी।

बंगाल, असम पांडुचेरी की जीत पर बेरला मंडल के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

बेमेतरा। भारतीय जनता पार्टी बेरला मंडल की मासिक बैठक बेरला नगर में सम्पन्न हुआ बैठक में समर्पण से संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। बैठक के बाद रेस्ट हाउस से कर्मा चौक तक पैदल रैली निकाल कर बंगाल, असम और पडुचेरी में भाजपा की जीत का जश्न मनाया, कार्यकर्ता और नागरिकों को मिठाई खिलाकर एवं फटाकों की आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया गया। इस अवसर पर सरगुजा संभाग प्रभारी एवं पूर्व विधायक अवधेश सिंह चंदेल ने कहा कि बंगाल, असम और पांडुचेरी की जीत पर समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई दिया और आगे कहा की बंगाल की जीत भय को पराजित कर विश्वास का जीत है ममता दीदी ने बंगाल में लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रहा था बंगाल में टीएमसी का गुंडा राज चरम पर था जिसका लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जरूरी था, भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दे दिया लोकतंत्र के बहाली के लिए बंगाल की जीत भाजपा के अनेकों कर्ताओं, जनभावना और मोदी जी के विकसित भारत को पूरा करने के तरफअग्रसर हो रहा है। पार्टी के निर्देशानुसार ढाई माह तक बंगाल के भातर विधानसभा में रह कर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में रह कर वहां की भयाव स्थिति को देखा हु कि टीएमसी के गुंडे कैसे लोकतंत्र का हत्या कर रहा था, मतदाताओं को मतदान करने से रोकते थे बंगाल में भाजपा की जीत से लोकतंत्र की बहाली होगा और बंगाल विकाश की नए तस्वीर बनायेगा। प्रदेश मंत्री संध्या परगनिया ने समस्त कार्यकर्ताओं को तीन राज्य बंगाल, असम और पांडुचेरी में जीत की बधाई दिया। तीन राज्यों के जीत पर मंडल अध्यक्ष डोमेन्द्र सिंह राजपूत ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दिया और कहा कि हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म भूमि बंगाल में कमल खुलने से बंगाल विकाश की रह में अग्रसर होगा। इस अवसर पर रोहित माहेश्वरी, नारायण पटेल, थानेश्वर साहू, यतीश द्विवेदी, गंगाधर साहू, विमला कुर्रे, संतोष साहू, कन्हैया वर्मा, युगल पाटिल, अरविंद ठाकुर, सिम्पू परगनिया, कमल साहू, जगदीश कुर्रे, राजू साहू, कन्हैया सेन, किशुन साहू, लक्ष्मी लता वर्मा, शिवझड़ी सिन्हा, किशन साहू, शैलेंद्री वर्मा, सरजू साहू, खम्मन श्रीवास, होलू साहू, नैनदास, गंगाधर साहू, गणेश चंदेल,रमेश सिन्हा, उकेंद्र साहू, लेखराम साहू, सुनील राजपूत, दिगेश्वरी साहू, लीलाराम साहू, मोहित साहू, डामन साहू, रघुवीर पिंटू सिन्हा, रामकुमार साहू, मनोज, प्रदीप, मयंक, राजेश, रोहित, पुखराज सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पश्चिम बंगाल, असम एवं पुडुचेरी में भाजपा की जीत पर विधायक ने कार्यकर्ताओ को दी बधाई

बेमेतरा। पश्चिम बंगाल, असम एवं पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड एवं ऐतिहासिक विजय पर बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी सहित प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने इसे लोकतंत्र की सशक्त जीत बताते हुए कहा कि यह परिणाम देश की जनता के अटूट विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी के कुशल मार्गदर्शन एवं लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का प्रतिफल है। विधायक साहू ने अपने विस्तृत सम्बोधन में कहा कि यह जीत केवल चुनावी सफलता नहीं, बल्कि जन-जन के विश्वास, उम्मीद और बदलाव की आकांक्षा की जीत है। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से चल रही भय, हिंसा, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति से जनता त्रस्त थी। आम नागरिक अपने ही राज्य में असुरक्षा और दबाव का जीवन जीने को मजबूर था। लेकिन इस बार बंगाल की जागरूक जनता ने लोकतांत्रिक ताकत का परिचय देते हुए उस कुशासन को सिरे से नकार दिया और भाजपा को प्रचंड बहुमत देकर स्पष्ट संदेश दिया कि अब राज्य में भय और अराजकता की राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल की पूर्व सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विगत वर्षों में राज्य में विकास की जगह वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया गया, जिसके कारण युवाओं के भविष्य, महिलाओं की सुरक्षा और आम जनता के अधिकारों की लगातार अनदेखी हुई। उद्योग, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में बंगाल पीछे होता गया। लेकिन अब जनता ने परिवर्तन का संकल्प लिया है और भाजपा के नेतृत्व में एक नए, सुरक्षित और विकसित बंगाल की नींव रखी है। साहू ने कहा कि भाजपा की यह ऐतिहासिक जीत इस बात का प्रमाण है कि देश की जनता अब केवल नारों से नहीं, बल्कि विकास, सुशासन और पारदर्शिता के आधार पर निर्णय ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जिस प्रकार से विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, उसका प्रभाव अब राज्यों के चुनावों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि असम और पुडुचेरी में भाजपा की शानदार सफलता यह दर्शाती है कि पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक भाजपा की स्वीकार्यता और जनसमर्थन लगातार बढ़ रहा है।

असम में विकास और स्थिरता की राजनीति को जनता ने सराहा है, वहीं पुडुचेरी में भी भाजपा के प्रति बढ़ते विश्वास ने यह साबित कर दिया है कि पार्टी की नीतियां सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हैं। विधायक साहू ने कहा कि भाजपा की यह विजय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र की विजय है, जिसने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का कार्य किया है। गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला और व्यापारी–हर वर्ग को केंद्र और भाजपा शासित राज्यों की योजनाओं से सीधा लाभ मिला है, जिससे जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है। उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से ही पार्टी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जनता के बीच काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह उनकी मेहनत, समर्पण और संघर्ष का परिणाम है। अंत में विधायक दीपेश साहू ने विश्वास जताया कि भाजपा की सरकारें पश्चिम बंगाल, असम एवं पुडुचेरी में विकास, सुशासन, सुरक्षा और समृद्धि का नया अध्याय लिखेंगी, और देश को एक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ाएंगी।

जिला पंचायत के सीईओ प्रखर चंद्राकर ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और पीएम हायर सेकेंण्डरी स्कूल का किया औचक निरीक्षण

गरियाबंद। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर चंद्राकर ने आज कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एवं पीएम हायर सेकेंडरी स्कूल, गरियाबंद का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दोनों संस्थानों में संचालित गतिविधियों, सुविधाओं तथा जारी कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बालिकाओं के लिए संचालित समर कैंप में पहुँचकर उन्होंने छात्राओं से विभिन्न गतिविधियों के बारे में पूछा और उन्हें अपनी रुचि के अनुसार कौशल सीखने तथा आगामी कक्षाओं की तैयारी में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। समर कैंप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अपने बीच पाकर छात्राएँ उत्साहित और प्रसन्न दिखाई दीं। उन्होंने अधीक्षिका को निर्देशित किया कि हॉस्टल परिसर में स्वच्छता, बच्चों के स्वास्थ्य तथा आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्यों पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसके पश्चात वे पीएम हायर सेकेंडरी स्कूल पहुँचे। जहाँ उन्होंने जारी निर्माण कार्य, शौचालय निर्माण एवं अन्य मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय-सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएँ। ताकि नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार कर नामांकन बढ़ाने के निर्देश भी प्रदान किए। निरीक्षण के दौरान डीएमसी शिवेश शुक्ला भी उपस्थित थे।

एक पेड़ माँ के नाम, एक सोखता संतान के नाम अभियान से हरियाली बढ़ाने और जल संरक्षण पर जोर

सांसद की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक संपन्न

दुर्ग। लोकसभा सांसद विजय बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद बघेल ने निर्देशित किया कि जिले में राज्य और केन्द्र शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो और योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएं। सांसद बघेल ने क्षेत्र के समग्र विकास, पर्यावरण संरक्षण और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने अधिक से अधिक पौधारोपण करने पर जोर देते हुए ÷एक पेड़ मां के नाम÷ और ÷एक सोखता संतान के नाम÷ अभियान के तहत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ जल संवर्धन को भी बढ़ावा मिल सके।

सांसद ने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों में पौधारोपण को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही नगरीय निकायों में बिल्डिंग परमिशन देते समय रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य रूप से प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने नगरीय निकायों के आयुक्तों को स्वयं क्षेत्र में जाकर कार्यों का निरीक्षण करने को कहा। साथ ही ग्राम पंचायतों में भी इस दिशा में गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। मनरेगा के तहत प्रत्येक गांव में काम शुरू करने तथा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत दिए जा रहे प्रशिक्षण की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल देते हुए अधिकारियों ने बताया कि निकुम, जेवरा-सिरसाखुर्द-भटगांव, चंदखुरी-कोलिहापुरी-पीसेगांव, अंजोरा-ढाबा, मोतीमपुर, ओदरागहन-सुरपा एवं कौही-रानीतराई समूह जलप्रदाय योजनाओं पर कार्य जारी है। सांसद ने लोगों को शुद्ध पेयजल जैसी समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए प्रमुखता से क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग करने को कहा।

सांसद बघेल ने कृषि कार्यों को ध्यान में रखते हुए समय पर खाद और बीज की उपलब्धता

सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बारिश से पहले पशुओं का टीकाकरण गांव-गांव में शिविर लगाकर प्राथमिकता से करने को कहा। इसके अलावा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण करने तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जर्जर सड़कों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुधारने के निर्देश भी दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को खराब सड़कों का निरीक्षण कर शीघ्र सुधार कार्य सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, सांसद आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण 1.0 एवं 2.0, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0, जल जीवन मिशन, पशुपालन, स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छ भारत मिशन, समग्र शिक्षा, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों की जानकारी दी।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत बजरंग दुबे ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत 28 फरवरी 2026 तक निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 100 प्रतिशत मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। वहीं मार्च 2026 से मई 2026 तक 65 प्रतिशत मानव दिवस उपलब्ध कराए गए हैं। सांसद श्री बघेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शेष अवधि में कार्यों में और तेजी लाई जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। उन्होंने प्रत्येक गांव में मनरेगा के तहत कार्य प्रारंभ करने और जरूरतमंदों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

जिले में 1550 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है, जिनमें से 1171 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु स्वयं के भवन में संचालित है। पीएम केयर्स चिल्ड्रन योजना अंतर्गत जिले में 17 बच्चे चिन्हांकित है जिन्हें योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। स्पान्सरशिप योजना अंतर्गत बच्चों को शिक्षा प्रदाय किए जाने प्रतिमाह चार हजार रूपए दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत जिले में 62 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है।

इस दौरान कलेक्टर अभिजीत सिंह ने सांसद द्वारा दिए गए निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित कर जिले में योजनाओं का कारगर क्रियान्वयन किये जाने आश्वस्त किया। वहीं इस दिशा में आवश्यक पहल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक के दौरान आयुक्त नगर निगम दुर्ग सुमित अग्रवाल, आयुक्त नगर निगम रिसाली मोनिका वर्मा, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कुलेश्वरी देवांगन, जनपद पंचायत सदस्यगण, समिति के सदस्य सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

उपभोक्ता आयोग ने परिवादी को दिलाई नई मशीन

बलौदाबाजार। दुकानदार द्वारा खराब मशीन को वारंटी के अंतर्गत सुधार कर प्रदाय नहीं किये जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार ने परिवादी को एजेंसी से नई मशीन दिलवाई। आयोग की अध्यक्ष रंजना दत्ता एवं सदस्यगण हरजीत सिंह चांवला व शारदा सोनी ने विकासखंड बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम पैजनी निवासी उपभोक्ता तिरिथ राम सोनवानी के प्रकरण एवं नियमों का गहनता से अध्ययन कर सम्बंधित मामले में विरोधी पक्षकार महालक्ष्मी ट्रेडर्स बलौदाबाजार को उपभोक्ता को मानसिक आर्थिक क्षतिपूर्ति तथा वाद-व्यय हेतु कुल 6000/-रूपये भुगतान का आदेश पारित किया गया तथा मशीन में सुधार कार्य मशीन निर्माता कंपनी वर्धा, नागपुर से परिवादी की संतुष्टी योग्य मरम्मत कराकर दिये जाने एवं संतुष्टी योग्य मरम्मत कराकर नहीं दिये जाने पर नया मशीन अथवा नया मशीन की वर्तमान कीमत दिये जाने का आदेश दिया गया। विरोधी पक्षकार महालक्ष्मी ट्रेडर्स बलौदाबाजार के संचालक परेश अग्रवाल ने आयोग के आदेश का त्वरित पालन करते हुये परिवादी को नया मशीन तथा मानसिक आर्थिक क्षतिपूर्ति तथा वाद-व्यय हेतु कुल 6000/-रुपये आयोग के माध्यम से प्रदाय किया।

विकास की वेदी पर बलि चढ़ेंगे गरीबों के आशियाने

रिसाली निगम के पास खाली जमीन के 4 विकल्प, फिर भी आम्बेडकर आवास पर नजर

जोरातराई के आम्बेडकर आवास को तोड़ने का विरोध, कलेक्टर से लगाई गुहार

भिलाई/रिसाली। नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड 37, जोरातराई में स्थित आम्बेडकर आवास को तोड़ने के नोटिस ने स्थानीय निवासियों की चिंता बढ़ा दी है। अस्पताल निर्माण के नाम पर करीब 79 परिवारों को विस्थापित करने की तैयारी का पुरजोर विरोध शुरू हो गया है। बुधवार को पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर कार्यालय पहुँचकर ज्ञापन सौंपा और आवास बचाने की गुहार लगाई।

25 साल पुराना है आशियानाप्त- प्रभावित निवासियों ने बताया कि ये आवास सन 2000 में बनाए गए थे, जहाँ लगभग ढाई दशक से अत्यंत गरीब परिवार रह रहे हैं। निगम प्रशासन ने हाल ही में इन मकानों को ढहाने का नोटिस थमाया है। बीते मंगलवार (5 मई) को जब निगम का दस्ता भारी पुलिस बल के साथ तोड़-फोड़ करने पहुँचा, तो महिलाओं और बुजुर्गों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया, जिसके बाद अमले को बैरंग लौटना पड़ा।

निवासियों ने सुझाए वैकल्पिक स्थान- कलेक्टर को सौंपे पत्र में वार्डवासियों ने स्पष्ट किया कि वे अस्पताल के निर्माण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन गरीबों के घर तोड़ना गलत है। उन्होंने प्रशासन को अस्पताल के लिए चार वैकल्पिक स्थान सुझाए हैं:

1. पुराना स्कूल परिसर की खाली जमीन।
2. बाग पारा मंच के पास उपलब्ध मैदान।
3. फाइव स्टार क्षेत्र की रिक्त भूमि।
4. राशन दुकान के सामने स्थित सरकारी जमीन।

कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग- निवासियों का कहना है कि प्रशासन बिना तोड़-फोड़ किए भी अस्पताल बनवा सकता है। उन्होंने मांग की है कि जब तक वैकल्पिक भूमि पर विचार नहीं किया जाता, तब तक तोड़-फोड़ की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि उनके सिर से छत छीनी गई, तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे।

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

भिलाई आईटीआई में 11 मई को प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन

दुर्ग। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) भिलाई द्वारा क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। आगामी 11 मई 2026, सोमवार को आदर्श शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जी.ई. रोड पावरहाउस भिलाई में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जाएगा।

आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भिलाई के प्राचार्य से प्राप्त जानकारी अनुसार यह मेला सुबह 09.30 बजे से प्रारंभ होगा। इसमें सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थी अपने साथ 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची, आईटीआई उत्तीर्ण अंकसूची एवं सर्टिफिकेट, नवीनतम रिज्यूम (बायोडाटा) और आधार कार्ड एवं अन्य आवश्यक मूल दस्तावेज के साथ मेला में उपस्थित हो सकते है। मेला के माध्यम से भर्ती हेतु नियोजक एसीसी लिमिटेड जामुल सीमेंट वर्क्स भिलाई द्वारा फिटर 03, वेल्डर 02, इलेक्ट्रिशियन 02, टर्नर 01, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 01, डीज़ल मैकेनिक 01, नियोजक एसीएमई ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड भिलाई द्वारा इलेक्ट्रिशियन 01, नियोजक सिम्प्लेक्स कास्टिंग्स भिलाई द्वारा फाउंड्रीमैन 04, फिटर 04, वेल्डर 04, टर्नर 02, नियोजक विष्णु केमिकल्स भिलाई द्वारा फिटर 10, इलेक्ट्रिशियन 03 और वोस्लोह बीके कास्टिंग्स लिमिटेड भिलाई द्वारा मशीनिस्ट 01, फिटर 03, कारपेंटर 01, फाउंड्रीमैन 02, मेसन 01 शामिल है।

अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र: गांव -गांव पहुंची बैंकिंग सुविधा, सालभर में 27करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन

बलौदाबाजार। बैंकिंग कार्य के लिये शहर न जाना पड़े बल्कि गांव में ही सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विगत वर्ष अप्रैल माह में प्रदेश में अटल डिजिटल सेवा केंद्र की शुरुआत की है। इस केन्द्र के शुरू होने से अब गांव में ही बैंकिंग सुविधा के साथ विभिन्न योजनाओं के तहत कार्ड, प्रमाण पत्र भी आसानी से प्राप्त हो रहे है। बलौदाबाजार -भाटापारा जिले में 381 गांव में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र संचालित है जिसमें एक वर्ष में 27 करोड़ 8 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। इसमें विकासखंड बलौदाबाजार के 76 केंद्रों में 8 करोड़ 56 लाख, भाटापारा के 69 केंद्रों में 4 करोड़ 94 लाख, कसडोल के 92 केंद्रों में 5 करोड़ 62 लाख,पलारी के 6 3 केंद्रों में 5 करोड़ 10 लाख एवं विकासखंड सिमगा के 81 केंद्रों में 2 करोड़ 93 लाख शामिल है। अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों ने बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीणों के घर के दरवाजे तक पहुँचा दिया है। इन केंद्रों के माध्यम से मुख्य रूप से आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए ग्रामीण अपने बैंक खातों से आसानी से लेन-देन कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन, किसान सम्मान निधि और मनरेगा की राशि निकालने में बुजुर्गों और किसानों को बड़ी राहत मिली है।बैंकिंग के साथ-साथ ये केंद्र ग्रामीणों को डिजिटल लेन-देन के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। एक वर्ष के भीतर 27 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी का प्रवाह सुगम हुआ है। इससे न केवल स्थानीय व्यापारियों को लाभ हो रहा है, बल्कि ग्रामीणों के समय और परिवहन पर होने वाले खर्च की भी बचत हो रही है।

दूषित पानी की सप्लाई से रामनगर मुक्तिधाम क्षेत्र में बीमारी का खतरा

स्वाभिमान मंच ने कलेक्टर से की शिकायत

भिलाई। भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 14, रामनगर मुक्तिधाम क्षेत्र में पिछले कई दिनों से हो रही दूषित और बदबूदार पानी की आपूर्ति ने जन स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है। इस गंभीर समस्या को लेकर 'छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच' ने कड़ा रुख अपनाते हुए दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन लाल साहू ने बताया कि वार्ड के निवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। नलों से मटमैला और दुर्गंधयुक्त पानी आ रहा है, जिसके सेवन से क्षेत्र में डायरिया, पीलिया और पेट संबंधी बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ गई है। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ रहा है।

निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप- पूरन लाल साहू ने कहा कि नगर निगम प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। पाइपलाइन में लीकेज या गंदगी मिलने की शिकायत के बावजूद अधिकारी मौन हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह आम जनता के मौलिक अधिकार 'स्वच्छ जल' का उल्लंघन है।

स्वाभिमान मंच की मांगें- प्रभावित क्षेत्र में तत्काल टैंकरों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की सप्लाई शुरू की जाए,पाइपलाइन के लीकेज को युद्धस्तर पर दुरुस्त किया जाए,लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर दंडात्मक कार्यवाही हो।

मंच ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही पेयजल व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो जनहित में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इस दौरान संगठन के प्रमुख पदाधिकारी और वार्ड के त्रस्त नागरिक उपस्थित थे।

सही दवा-शुद्ध आहार अभियान : तंबाकू व खाद्य विक्रेताओं पर सघन जांच

दुर्ग । राज्य शासन द्वारा 11 मई तक ''सही दवा-शुद्ध आहार - यही छत्तीसगढ़ का आधार'' थीम के अंतर्गत 15 दिवसीय सघन जांच अभियान संचालित किये जाने हेतु प्रत्येक जिले में कार्यरत खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है।

औषधि शाखा द्वारा अभियान के दसवें दिवस चतुर्थ चरण के प्रथम दिवस आज 06 मई को कोटपा एक्ट के अंतर्गत जिले के जुनवानी, नेहरू नगर एवं स्मृति नगर क्षेत्र में तम्बाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के बारे में जन जागरूकता लाते हुए जिन पान ठेलों एवं होटलों में कोटपा एक्ट के उल्लंघन पाए गए ऐसे 32 जगहों पर औषधि निरीक्षकों एवं पुलिस दल द्वारा नियमानुसार चालानी कार्यवाही की गई। कोटपा एक्ट के तहत् इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। इसी प्रकार खाद्य शाखा द्वारा जिले में संचालित कंफेक्शनरी, कैण्डी एवं चॉकलेट विक्रेता जिसमें मेसर्स पूजा स्वीट्स, मेसर्स जय बाबा ट्रेडर्स, गोपी स्वीट्स, लक्की स्वीट्स, लिंक रोड, पावर हाउस, भिलाई एवं मेसर्स मनोज कंफेक्शनरी, ए.एन. प्रोडक्ट, भिलाई-03, की जांच/निरीक्षण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् किया गया, जिसमें संचालकों को उचित साफ-सफाई के साथ व्यवसाय संचालित किये जाने एवं साथ ही साथ निर्देशित किया गया कि नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

"विकसित कृषि संकल्प अभियान" का दुर्ग में हुआ भव्य शुभांरभ

किसानों को उन्नत तकनीकों और योजनाओं की दी जाएगी जानकारी, वैज्ञानिक करेंगे गांव-गांव संवाद

दुर्ग। जिले में 05 से 20 मई 25 तक ''विकसित कृषि संकल्प अभियान'' खरीफ 2026 प्रारंभ होने के पूर्व कृषि कार्यो की तैयारी आधुनिक तकनीकों, किसानों के लिए उपयोगी विभिन्न विभागीय योजनाओं फसलवार अनुशंसित मात्रा अनुसार संतुलित उर्वरक के प्रति जागरूक करने तथा किसानों के द्वारा फीडबैक के आधार कृषि अनुसंधान हेतु आवश्यक दिशा निर्धारण के उद्देश्यों से अभियान चलाया जाएगा।

जिले में इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछलीपालन विभाग के अधिकारियों को शामिल कर 02 टीमें प्रति विकासखण्ड हेतु बनाई गई हैं। प्रत्येक टीम एक दिन में एक ग्राम में जाएगी एवं जिले में कुल 72 ग्रामों में शिविर आयोजित कर किसानों से सीधा संवाद करेंगी। साथ ही किसानों से खेती संबंधी समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान बनायेगी। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछलीपालन विभाग के अधिकारी विभागीय योजनाओं की जानकारी किसानों के साथ साझा करेंगे, जिससे किसान शासन की योजनाओं का आसानी पूर्वक लाभ ले सकें।

विकासखण्ड पाटन हेतु रथ की रवानगी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरूण साव एवं सासंद दुर्ग विजय बघेल विकासखण्ड दुर्ग हेतु रथ को तथा विकासखण्ड धमधा हेतु रथ की रवानगी अहिवारा विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया।

इस अवसर पर आई.सी.ए.आर./कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकगण, कृषि/ उद्यानिकी/ मत्स्य पालन/पशुपालन विभाग के अधिकारीगण तथा कृषकगण उपस्थित रहें। जिले के किसानों से अपील की यह है कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेकर उन्नत कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करें तथा शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ लें और वैज्ञानिकों से प्रत्यक्ष संवाद कर अपनी कृषि संबंधी समस्याओं का निराकरण पायें।

स्वत्वाधिकारी , प्रकाशक, एवं मुद्रक ज्वाला प्रसाद अग्रवाल द्वारा असमा पब्लिशर्स प्रा. लि. जयस्तंभ चौक, रायपुर, पिन - 492001 छत्तीसगढ़ से मुद्रित एवं झुलेलाल मंदिर के पीछे, पाटनकर कालोनी, सिंधी कालोनी, दुर्ग पिन- 491001 (छ.ग.) से प्रकाशित।
संपादक - ज्वाला प्रसाद अग्रवाल । e mail - jwalaexpress@gmail.com , मोबाईल- 9993590905, 7000489995